about that. The doctors should also realise their responsibility towards the people, in general, and also to their own oath, and the Government should also see what is fair and the promises, if any, which had been made, should be fulfilled and adhered to. In this spirit, I think, this is a question which is beyond dispute because it affects the health and the life of the people as well as the confidence and the credibility of the professionals, and that is why, certainly, I am of the view that this matter should received the cutmost attention of the Government.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर सभापति जी, विपक्ष के नेता डा० मनमोहन सिंह और माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं और विचार प्रकट किए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। 15-16 दिन से स्ट्राइक हो जाने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जो व्यवस्था है चिकित्सा की, वह अस्त-व्यस्त हो गई है। मरीज़ों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से ले और डाक्टरों से बात करके उनकी हड़ताल को समाप्त कराएं और जो उनकी मांगें सही हैं और जायज़ हैं, सरकार को उन्हें मान भी लेना चाहिए।

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Mr. Chairman, Sir, I fully associate myself with the views expressed by Dr. Manmohan singh. Since this is very prestigious institution of the country, the Government should solve the dispute immediately and the whole thing should be reviewed properly. Thank you, Sir.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I whole heartedly associate myself with the views expressed by Dr. Manmohan Singh. Sir, I earnestly appeal to the Government to invite the striking doctors and see that a settlement is mde amicably. Thank you.

SHRI S. VIDHUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, we demand a *suo motu* Statement from the Government, giving particulars of the agreement already made. What are the issues that have been settled? What are the issues still pending? Sir, the demands made by the doctors can also be mentioned in the Statement to be placed before us. We request the doctors also to consider the plight of the common man. They should talk to the Government, and an amicable solution should be found, by mutual consultation. A *suo motu* Statement is essential.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the Motion of Thanks on the President's Address.

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): सर, आन्ध्र प्रदेश में जो...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. *(Interruptions)*. Nothing will go on record. *(Interruptions)*. I am not giving permission. *(Interruptions)*. No, no. *(Interruptions)*. I have not given permission. *(Interruptions)*. Now, Prof. Vijay Kumar Malhotra.

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS

PROF VIJAY KUMAR MALHOTRA (Delhi): Sir, I beg to move that an Address be presented to the President in the following terms:

> "That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 22, 1999."

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी तीन दिन पूर्व पाकिस्तान की अपनी ऐतिहासिक यात्रा से लौटे हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के केवल 12 घंटे पूर्व लौटने के कारण राष्ट्रपति के भाषण में उनका वृत्त बहुत संक्षेप से आया है। मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री जी शीघ्र ही अपनी पाकिस्तान यात्रा के संबंध में पूरा वृत्त इस सदन में रखेंगे और उस पर इस सदन को विचार करने का मौका मिलेगा। प्रधान मंत्री जी की यात्रा ऐतिहासिक और युगान्तकारी थी. इसलिए नहीं कि बस के द्वारा भारत का पहला प्रधान मंत्री पाकिस्तान गया था। मुझे उन के साथ यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अमृतसर से लेकर लाहौर तक के बीच में सड़कों पर दोनों ओर खड़े हजारों लोग, उनके दिलों की भावनाओं का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता, वह शब्दातीत अनुभव था और दोनों प्रधान मंत्रियों ने जो भाषण दिए वह भी अपने में ऐतिहासिक भाषण थे।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी को लाहौर में जो सिविक रिसेप्सन दिया गया उसके जवाब में उन्होंने जो

भाषण दिया था वह भाषण भी बहुत ऐतिहासिक था। मेरे साथ बहुत से पाकिस्तान के राजनेता बैठे थे, बहुत से व्यवसायी बैठे थे, बहुत से उद्योगकर्मी बैठे थे और बहुत से अधिकारी भी बैठे थे, सबका एक-सा मत था और जो शब्द उन्होंने कहे वे हैं—क्या तकरीर है, क्या ईमानदारी है, क्या साफगोई है। प्रधान मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि हम पाकिस्तान...**(व्यवधान)**...

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या प्रधान मंत्री की यात्रा पर बोल रहे है?

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): पैराग्राफ 8 उसी से संबंधित है। ...**(व्यवधान)**...

कुमारी सरोज खापर्डे: मैंने आपसे नहीं पूछा है, मैंने चेयर से पूछा है। ...**व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): सब लोग शुरू से शुरू करते हैं और ये आखिर से शुरू करते हैं। ...**व्यवधान**)...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: जी, हां इसमें वर्णन है विदेशों से अपने संबंध सुधारने का और प्रधान मंत्री जी की लाहौर यात्रा का वर्णन इसके अन्दर है। आपको यह बात क्यों चुभ रही है, मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं उसका भी वर्णन करूंगा, मैं उसके ऊपर आना चाहता हूं।

†श्री मोहम्मद सलीम: सब लोग शुरू से शुरू करते हैं और ये आखिर से शुरू करते हैं... "مداخلت"...†

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि प्रधान मंत्री जी ने साफतौर पर कहा है कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते थे। देश का विभाजन हुआ तो हमारा दिल जख्मी हुआ था, परन्तु जख्म भर गए, दाग रह गए और यह दाग हमें याद दिलाता है कि हमें दोनों देशों को मिलकर चलना है, शांतिपूर्वक चलना है। यह प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है कि प्रधान मंत्री जी की यात्रा से क्या उपलब्धि हुई? मैं कहना चाहता हूं कि उपलब्धि को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि पहली बार दोनों प्रधान मंत्रियों ने मिलकर जो पहले तीन-तीन युद्ध हुए हैं उसके बाद शांति का मौका देने की बात कही है। दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस बात की घोषणा की है कि सारी दुनिया आणविक यंत्रों से विहीन होनी चाहिए। दोनों ने इस बात की भी घोषणा की कि शिमला समझौते की लैटर एंड स्प्रिट के अंतर्गत हम अपनी मसायल हल करेंगे और जो तीसरी ताकतें हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच माध्यस्थता करने के लिए तड़प रही थी उनके सारे मनसूबे छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। लोग वीसा लेकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच उस त्रासदी में लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर गये थे। मैं भी 52 साल के बाद अपना घर देखना चाहता था। मैं भी उन गलियों में घूमना चाहता था, उन स्कूल और कालेजों को देखना चाहता था जिनमें मैंने 16 साल बिताये थे। हर आदमी इसी दृष्टि से पाकिस्तान जाना चाहता है और पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान आना चाहते हैं। हमारे धर्म-स्थान वहां पर हैं और उनके धर्म-स्थान यहां पर हैं परन्तु वीज़ा बहुत बुरी हालत में है, मिलना कठिन है। उसकी शर्तें इतनी अमानवीय हैं कि रोज दस बजे पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करे, यह सब उसके अंदर आता है। उसके ऊपर भी दोनों प्रधान मंत्रियों ने कहा कि वीसा की शर्तें सामान्य की जाएं और लोगों को आने-जाने की बहुत सुविधाएं होनी चाहिएं। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि युद्ध के दौरान 1971 से वहां पर जो युद्धबन्दी कैदी हैं, अमानवीय दृष्टि से वहां पर स्थित हैं उनके लिए एक कमीशन बने। इसके अलावा और बहुत सी बातों का वहा पर फैसला हुआ है।

चेयरमैन साहब, मैंने कहा कि उस का पूरा वृत्त आपके सामने प्रधान मंत्री जी रखेंगे। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने सब प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने की घोषणा की। यह ठीक है कि जिस दिन प्रधान मंत्री जी शांति का अलख जगा रहे थे, आई॰एस॰आई॰ ने जम्मू में 26 हिन्दुओं का नरसंहार किया। प्रधान मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से कहा और इस बात का आग्रह भी किया कि इस प्रकार के नरसंहार बन्द होने चाहिएं। पाकिस्तान सरकार यह कहकर उससे बच नहीं सकती कि उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। प्रधान मंत्री जी की पाकिस्तान यात्रा और उससे जो रिश्ते सुधर रहे थे, उन रिश्तों के सुधरने की छाया में यह अधिवेशन हो रहे हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री जी की यात्रा को आज सारी दुनिया सराह रही है। इनको और नवाज शरीफ दोनों को शांति नोबेल पुरस्कार देने की बात हो रही है। य॰एन॰ओ॰ के जनरल सेक्रेटरी ने भी उस बात का उल्लेख किया है। अपने देश में कांग्रेस ने इसके बारे में अपना रवैया शांत रखा है। उसका कोई बहुत स्वागत नहीं किया है। इनको यह बात अखर रही थी कि इसकी छाया में यह अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा और उसकी उपलब्धियां छाई रहेंगी। ऐसा लगता है उन्होंने यह सोचकर कि कैसे ध्यान बंटाया जाए, कैसे पाकिस्तान की

†[ ]Transilteration in Arabic Script

यात्रा को छोड़कर किसी और सवाल पर लाया जाए, पूरी तरह से शीर्षासन करके, पूरी तरह से उलट-फेर करके अपनी घोषित नीतियों के खिलाफ यह कहा कि बिहार के अंदर सरकार ने राष्ट्रपति राज लागू किया ...**(व्यवधान)**...

कुमारी सरोज खापर्डे: आप कह रहे हैं कि अत्यन्त दुख की बात है, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा; आपने कांग्रेस की चुप्पी के बारे में कहा। कांग्रेस वाले स्थिति में है कि आपको जवाब दे सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: अभी आप जवाब देंगे, मुझे मालूम है। ....**(व्यवधान)**...

कुमारी सरोज खापर्डे: कल हमारी नेता सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी इन-पार्लियामेंट में इसका उल्लेख किया और प्रधान मंत्री को बधाई दी थी। आप इसको इगनोर कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस से किस तरह से बात कहनी चाहिए, पहले आपको यह सोच लेना चाहिए। यह बात नहीं है कि हम खामोश रहेंगे और आप बोलते जायेंगे, यह क्या बात हुई?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, बिहार में दलितों के नरसंहार पर कांग्रेस की अध्यक्ष जाती हैं और इस बात की घोषणा करती हैं कि बिहार में राबड़ी सरकार रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी खुलेतौर पर उसका स्वागत करती है, कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी इसका स्वागत करती है कि राष्ट्रपति राज लागू हो। कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीएम वहां पर बन्द करती हैं, धरना देती हैं और सरकार के खिलाफ पूरे का पूरा आंदोलन चलाते हैं। जब बिहार में राष्ट्रपति राज लागू हुआ ...**(व्यवधान)**... राष्ट्रपति राज लागू होने के बाद ....**(व्यवधान)**.. Not me. You supported. You opposed the Government.

आपने धरने दिये, आपने बिहार बन्द किया। आपने बिहार के अंदर लालू सरकार और राबड़ी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाए।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: देखिए, हर पार्टियों के प्रतिनिधि यहां बोलेंगे। आप अपनी बात कहिएगा। इसका जवाब दे दिया जाएगा। उनको बोलने दीजिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, ...**(व्यवधान)**...

SHRI SANATAN BISI (Orissa): It should be according to the speech.

MR. CHAIRMAN: It is referred to in the speech.

श्री सनातन बिसि: कांग्रेस प्रेसीडेंट ने क्या किया, क्या इसका रेफरेंस स्पीच में है?. ..**(व्यवधान)**...

यहां आप यह बोलिए कि इस सीरियल नंबर पर, इस पेज पर यह बोला है

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, बिहार में राष्ट्रपति राज...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: उनको बोलने दीजिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की कांग्रेस पार्टी क्यों इसके ऊपर अचानक वोल्टफेस कर गई, क्यों अचानक पूरी तरह से बदल गई? क्योंकि 12 तारीख ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: इसका जवाब दें देंगे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: 12 फरवरी से लेकर आज 24 फरवरी है, 12 दिन में कांग्रेस पार्टी एकदम बदल गई। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। राष्ट्रपति राज लागू करने के बाद इसका विरोध नहीं किया लेकिन कल अचानक सी०डब्लू०सी० की मीटिंग के अंदर इसका विरोध कर दिया और उसी वक्त जब...

कुमारी सरोज खापर्डे: किस बात का विरोध किया? कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया जिस तरीके से वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जिस तरीके से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया उसका विरोध किया। आप पढ़िए ठीक से। कांग्रेस ने ...**(व्यवधान)**...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया जब कि बिहार के अंदर अरबों रुपये का घोटाला हुआ है, अराजकता ही अराजकता है, नरसंहार ही नरसंहार हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... वहां पर दंगा-फसाद, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और इन सारे कांडों के बाद अरबों रुपयों का घोटाला है। यह सब कुछ होने के बाद भी ...**(व्यवधान)**... सभापति महोदय, यह जो बीच बीच में...

श्री सभापति: आप अपनी बात कहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: तो मैं यह कह रहा था कि कि बार बार यह सब होने के बाद भी अगर धारा 356 नहीं लग सकती तो किस पर लग सकती है? बाद में आप ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, देखिए।

MR. CHAIRMAN: Generally, it is the decorum of the House that if a person initiates, he should notbe interrupted. A very party will have a chance. They can reply. It is better not to interrupt. They should hear you and you should hear them.

कुमारी सरोज खापर्डेः एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कहें वह ठीक ढंग से कहें। आप को इस तरह की उल्टी सीधी बातें हमारी पार्टी के लिए नहीं करनी चाहिए।

श्री सभापतिः आपकी पार्टी के बारे में आपकी पार्टी के लोग जवाब दे देंगे।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः सभापति महोदय, बिहार में राष्ट्रपति राज लागू किया गया है। राष्ट्रपति राज लागू करने की इससे बेहतर कोई परिस्थिति वहां पर नहीं थी। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में कांग्रेस पार्टी, जो बाकी पार्टियों के साथ धारा 356 का विरोध कर रही है तो इसी कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में विभिन्न राज्यों में 90 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया है। सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली और आज कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धारा 356 का उपयोग, जो वहां पर किया गया है यह ठीक नहीं है। सभापति महोदय, अगर कांग्रेस पार्टी दलितों पर अत्यधिक से भयंकर और भीषण से भीषण अत्याचार का समर्थन करना चाहती है तो यह उनको मुबारक हो। आज बिहार को कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की सी॰डब्लू॰सी॰ ने बिहार में कांग्रेस का क्रियाकर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां पर कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी गई है कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी जिससे दलितों पर होने वाले ये भीषण अत्याचार ये सारी परिस्थितियां...**(व्यवधान)**...

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): You justify your action and then criticise her. You have started from the other end. *(Interruptions)*. You justify your action. You are not justifying your action.

(Interruptions).

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः सभापति जी, हमारी शायद गलती इतनी थी कि हमने कांग्रेस पार्टी की सार्वजनिक घोषणा पर विश्वास कर लिया। कांग्रेस की सार्वजनिक घोषणा के पीछे छिपा हुआ चेहरा हमने नहीं देखा। हम समझ रहे थे कि जो कांग्रेस कह रही है वह सच है। हमें मालूम है कि राज्य सभा में हमारा बहुमत नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करने वाली थी तो निश्चित तौर पर हम उसे पास नहीं करा सकते थे। परंतु हमने शायद गलती की कि कांग्रेस पार्टी की सार्वजनिक घोषणा और सी॰पी॰आई॰, सी॰पी॰आई॰(एम), जनता दल की घोषणाओं पर विश्वास कर लिया था। हमें मालूम था और हमें जानना चाहिए था कि Frailty thy name is Congress; immorality thy name is Congress.

कांग्रेस के लोग जो यहां पर.....

कुमारी सरोज खापर्डेः यह क्या बात हुई ....**(व्यवधान)**

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं बोला....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डेः सर इस तरह के भाषण हमें खामोश नहीं कर सकते। *(Interruptions)*. This is not a public speech. *(Interruptions)*. This is not a public speech. *(Interruptions)*. We will listen to you. But don't say all these things against the Congress party. *(Interruptions)*.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, we must understand the scope of the discussion on the President's Address. I would like to refer to 'Kaul & Shakdher' on this point. I would like to quote only one sentence. On page 189, 'Kaul & Shakdher' talks about limitations. It says, "Only limitations on the President's Address are that the Members cannot refer to matters which are not the direct responsibility of the Government of India". That is the limitation on each Member of the House in respect of the discussion on the President's Address. *(Interruptions)*. Sir, if you look at 'Kaul & Shakdher' it is clear that he cannot talk about matters which are not the direct responsibility of the Government of India. Therefore, ...*(Interruptions)*.

PROF. VIJAY KUKAR MALHOTRA: I am talking about Bihar. *(Interruptions)*. बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया है मैं उसके बारे में बोल रहा हूं। आप अपने भाषण में जवाब दे देना।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, if I may be permitted ...*(Interruptions)*. What postures the Congress party took, why and how.... is not the concern of the hon. Member when he is disucssing the President's Address. He cannot refer to the Congress party in this context.

MR. CHAIRMAN: That is all right. It is nota point of order.

SHRI KAPIL SIBAL. Sir, it is a point of order.

MR. CHAIRMAN: Nom it is not a point of order. *(Interruptions)*. Please quote the rule.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am quoting rule 15.

SHRI SANATAN BISI: Sir, rule 15 is clear. It says, "on such day or days or part of any day, the Council shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks...". They cannot raise extraneous matters. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Para 59 of the President's Address refers to the Bihar situation. Therefore, he can talk about that. *(Interruptions)*.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir..... *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Why are you talking about this unnecessarily? *(Interruptions)* No, that is why, you are informed.

The Book on 'Rajya Sabha At Work' mentions on page 185 and I read:

> "The scope of the discussion on the Motion of Thanks is very wide and Members are at liberty to speak on any matter of national or international importance. The general limitations, however, that while speaking, a Member cannot cast reflections on persons in high authority or on the Members of the other House or bring in the name of the President or refer to matters which are *sub judice* or pending consideration of a Parliamentary Committee, apply to the discussion on the Motion of Thanks also."

So, there is nothing wrong about it.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ यह बता रहा था। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा। मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने बिहार में राष्ट्रपति राज क्यों लगाया? बावजूद इसके यह जानते हुए कि हम यहां मेजोरिटी में नहीं हैं, यह हमें पहले ही मालूम था, मैं यह कह रहा हूं कि हमने भरोसा कर लिया, गलती कर ली, इनकी सार्वजनिक घोषणाओं का विश्वास कर लिया। अब 12 फरवरी के बाद क्या हुआ? 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 12 दिनों के बीच में क्या हुआ? एक तो यह हुआ कि पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा हो गई। दूसरा क्या यह संयोग है या क्या कोइनसीडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट बोफोर्स कांड में क्वातरोची को यहां पर पेश करने की आज्ञा देती है और कांग्रेस पार्टी अपना रेजोल्यूशन बदल देती है, अपना सारा मंतव्य बदल देती है।

कोई ऐसा संयोग हो गया कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि क्वत्रफातरोची को बोफर्स कांड में आना चाहिये बोफर्स कांड में जो लोग शामिल थे, उनके उपर यहां पर मुकदमा चलाना चाहिये। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह गई तो कठिनाई पैदा होगी। उस दिन पूरा शीर्षासन कर के, वोल्टेफेस कर के बिहार के अन्दर लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लिया जिसके लिए कांग्रेस पार्टी यह कह रही थी कि उसका शासन वहां खत्म करना सब से ज्यादा जरूरी है लेकिन आज इकट्ठे हो गये हैं **(व्यवधान)**

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, what is this? *(Interruptions)*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): He is not a Member of this House.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: हमने क्यों इन पर भरोसा किया? मैं यह कहना चाहता हूं कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की इन घटनाओं पर राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चिन्ता प्रकट की है। हत्या, बलात्कार, धार्मिक तोड़फोड़ निंदनीय है और राष्ट्रपति जी ने उसकी भी बहुत निंदा की है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार है..**(व्यवधान)**

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ..**(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सॉरी, उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार है। उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार है और दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकारें है। वहां पर ज्यूडिशियल कमीशन बने है, उनकी जांच हो रही है और उसके प्रतिफल सामने आएंगे **(व्यवधान)** परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना दुष्प्रचार किया गया, इतना मिथ्या बोला गया, झूठ बोला गया, इतना अनर्गल प्रचार किया गया कि सारे देश को बदनाम कर के रख दिया गया। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ तीन चार कोटेशंस आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। केवल उन्हीं बातों का ज़िक्र करूंगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। एक है फ्रांस की सब से ज्यादा बिकने वाली पत्रिका है (ला फ्रिगारो उसमें साऊथ एशियन कोरेसपोंडेंट फ्रेंकोइस कार्टियर के एक आर्टिकल के कुछ उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं **(व्यवधान)** महोदय, यह हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है। **(व्यवधान)** महोदय, यह हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है। **(व्यवधान)** वह भी क्रिश्चियन है **(व्यवधान)** कांग्रेस के अखबार में यह छपा है। **(व्यवधान)** The South Asian correspondent, Francois courtier, says: "While there is no doubt that the ghastly murder...*(Interruptions)*

MISS SAROJ KHAPARDE: Which magazine are you referring to? *(Interruptions)*

SHRI KAPIL SIBAL: You have to mention the name. Then only can you refer to it.

MR. CHAIRMAN: Please mention the name of the magazine...*(Interruptions)*

MISS SAROJ KHAPARDE: What is the name of the magazine? *(Interruptions)*

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: It is *La Figaro*. *(Interruptions)* I am only quoting from that article.

यह क्या बात है? मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं कि इनका आर्टिकल क्या है। ..**(व्यवधान)**

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka) : Show us the front page of the magazine.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, यह आर्टिकल "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपा है। फिर जागरण में छपा। उसी आर्टिकल को मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।...**(व्यवधान)**

SHRI JANARDHANA POOJARY: He has to show us the front page of the magazine. *(Interruptions)*

MISS SAROJ KHAPARDE: Please tell us the name of the magazine.

श्री सुरेश पचौरी: यह भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका से पढ़ रहे हैं...**(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: "हिन्दुस्तान टाइम्स" के एडिटोरियल पेज पर, उसके नीचे यह आर्टिकल छपा है, जिसको इसमें री-प्रोड्यूस किया गया है हिन्दी में भी है और अंग्रेजी में भी है।...**(व्यवधान)**

MISS SAROJ KHAPARDE: You tell us the name of the magazine. *(Interruptions)*

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैं कह रहा हूं कि यह "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एडिटोरियल पेज के नीचे छपा है। उसको इन्होंने...**(व्यवधान)** यह क्या हो रहा है?...**(व्यवधान)** I am only quoting from the article.

अगर कोई आबजैक्शन करता है तो बताए ...**(व्यवधान)**

SHRI JANARDHANA POOJARY: You tell the House the name of the magazine.

कुमारी सरोज खापर्डे: उस मैगज़ीन का पत्ता तो बताइये और कौन सी मैगज़ीन आप पढ़ रहे हैं?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: यह "जागरण" में भी छपा है। ...**(व्यवधान)** यह बी०जे०पी० वाली मैगज़ीन है। ...**(व्यवधान)** आप इसके आर्टिकल को कहिए कि नहीं है...**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: आप मैगज़ीन का नाम तो बताइये?...**(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: यह क्या बात कर रही हैं।...**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: बात मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूं।...**(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: बी०जे०पी० के पेपर ने उसको कोट किया है पूरा का पूरा उसको मैं पढ़ रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: मैगज़ीन का नाम बताइये? ...**(व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): what she is asking is this. Now, you are quoting from somewhere. All that we want to know is the name of the magazine from which you are quoting and the date of the publication of the article.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am telling you.

यह आर्टिकल "हिन्दुस्तान टाइम्स" के एडिटोरियल पेज पर छपा है। उसके बाद "जागरण" अखबार ने छापा । उसमें से ले करके इस बी०जे०पी० के मैगज़ीन ने। ....**(व्यवधान)** बी०जे०पी० की मैगज़ीन मैं बता तो रहा हूं...**(व्यवधान)**

MISS SAROJ KHAPARDE: What is the name of the magazine?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: It is *BJP Today.*

उसने इसको रीप्रोड्यूस किया है।...**(व्यवधान)**

MISS SAROJ KHAPARDE: what is the name of the magazine? ...*Interruptions*... आप उस मैगज़ीन का नाम तो बताइये? ....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: यह तो उन्होंने बता दिया है। उन्होंने "बी०जे०पी० टुडे" कह तो दिया है। ...**(व्यवधान)**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: "बी०जे०पी०टुडे" मैगज़ीन ने उसको रीप्रड्यूस किया है। ...**(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: He has said it. Now, you can go ahead.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, आर्टिकल में जो छपा है वह महत्वपूर्ण है या किस मैगज़ीन ने उसको रीप्रोड्यस किया वह महत्वपूर्ण है? इसके आर्टिकल में लिखा है:

> "While there is no doubt that the ghastly murder of Grahm Steward Stains, the Australian missionary, and his two innocent sons should be universally condemned and that culprits should be severely punished, the massive outcry as evoked in the Indian Press raises several important questions".

for which, an Indian, who dares utter the following statement, would immediately be identified with the Sangh Parivar —

> "is the life of a whiteman more important and dear to the Indian media than the lives of a hundred Indians? Or, to put it differently, is the life of a Christian more sacred than the life of many Hindus? It would seem so...."

DR. BIPLAB DASGUPTA: What do you mean? What is this? (*Interruptions*)

SHRI JANARDHANA POOJARY: He is quoting somebody. What has that got to do with the issue? (*Interruptions*)

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): What is the point that you are trying to make? Don't read things like this. (*Interruptions*)

DR. BIPLAB DASGUPTA: Every human being is important, whether he is a Hindu or a Chirstian or anybody.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैं अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं कह रहा हूं। I am not saying that I am saying this. यदि मैं कहूं, तो कहिए। मैं तो उसको पढ़ रहा हूं। ....**(व्यवधान)**

DR. BIPLAB DASGUPTA: Why do you compare one Christian with 100 Hindus?...(*Interruptions*)...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: आप उन से पूछिए न।

You go and ask him.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Many articles have been written in various magazines. Can he do that? It is not his view. It has been said by somebody else. How can he quote it here?

कुमारी सरोज खापर्डे: हिंदुस्तान में इतनी मैजीन्स हैं और उनमें इतना कुछ लिखा हुआ है, अगर आप को इंटरेस्ट है तो आप उन को कोट करिए।·उन्हें छोड़कर आप विदेश की मैगजीन्स को कोट कर रहे हैं?

You quote those magazines. Why are you quoting *videshi* magazines here?...(*Interruptions*)...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am only quoting others, I am not quoting you ...*(Interruptions)*...राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह जो घटनाएं हुई हैं, यह बहुत निंदनीय है, पर इन घटनाओं को सारी मायनोरिटीज के खिलाफ इस्तेमाल न करें।...(व्यवधान)...उस के आगे उन्होंने लिखा है ...(व्यवधान)... जो आप से कहना चाहता था, वह सुन लीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: "The massive outcry on the atrocities against the minorities raises also doubts about the quality and integrity of Indian journalism. Take, for instance, the rape of four nuns in Jhabua. Today the Indian Press and the foreign correspondents are still reporting that it was a religious rape. Yet, I went to Jhabua and met the four adorable nuns who themselves admitted along with their Bishop George Anakil that it had nothing to do with religion. It was the doing of a gang of tribals known to perpetuate this kind of hateful acts on their own women. Yet, today the Indian Press, the Christian hierarchy and the politicians continue to include the Jhabua rape in the list of atrocities against the Christians." ...(व्यवधान)...

SHRI M.J VARKEY MATTATHIL (Kerala): You prove it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष महोदय, उस ने खुद जाकर यह कहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने वहां जितने लोगों को गिरफ्तार किया। ...(व्यवधान)... मध्य प्रदेश की सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उस में क्रिश्चियंस भी शामिल थे। ...(व्यवधान)...मध्य प्रदेश की सरकार ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन में ईसाई भी थे। सर, इस में आगे जो लिखा है, उस से मेरे ये भाई दुखी होंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः उन्हें बोलने दीजिए।

SHRI K.M. KHAN (Andhra Pradesh): We should state the facts to the House. ...*(Interruptions)*...

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: He said, "In Wynad, in northern Kerala, it was reported that a priest and four women were beaten up and a Bible was stolen by fanatical Hindus, and an FIR was lodged. The Communists took out processions all over the Kerala to protest against the atrocities..."

SHRI A VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Sir,...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Your party will also yet a chance.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: "And the Press went gaga. yet, an intrepid reporter from Calicut office of the *Indian Express* found out nobody was beaten up and the Bible was safe. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. you will get a chance to speak. Then you can reply to these points.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: "...it was too late. The damage was done and it is still being made use of by the enemies of India.

वह आगे पूछता हैः

"Why do the Indians always reflect a westernised point of view? Why do India's intellectual elite, the majority of which happens to be Hindus, always come down so hard on their own culture, their own religion, their own brothers and sisters? Is it because of an eternal feeling of inferiority which itself is a legacy of British colonisation? Is it because they consider Hindus to be inferior beings? Is it because the Indian Press is still deeply influenced by Marxists and Communists..." ...*(Interruptions)*...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, the President's Address talks about curbing such incidents. But, he is

preaching fundamentalism here. Why is he quoting somebody else? ...*(Interruptions)*...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति जी, मैं सारा आर्टिकल नहीं पढ़ता, मैं उस की आखिरी बात पढ़कर खत्म कर देता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री सुरेश पचौरी: सर, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उस पर अपना अफसोस जाहिर किया है और ये अल्पसंख्यकों पर जुल्मों की दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: आप बोलेंगे तब कह दीजिए।

श्री सुरेश पचौरी: अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में अफसोस जाहिर किया है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: आखिरी बात पढ़ देता हूं , यह बहुत कंडेमनिंग है आप के लिए। ये चार लाइंस पढ़ देता हूं।

"Whatever it is, harm is done because even though it is not the truth which has been reported from Jhabua, from Wynad or from the Keonjhar district of Orissa, it has been far from truth, and it has been believed to be the Marxists."

श्री सुरेश पचौरी: महोदय, ये बी०जे०पी० टुडे को कितनी देर पढ़ेंगे? महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने देश के विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की है और आप बी०जे०पी० टुडे पढ़ रहे हैं। महोदय, आप उन्हें बी०जे०पी० टुडे पढ़ने के लिए कितनी बार अलाउ करेंगे? ये अन्य पॉइंट्स के संबंध में बोलें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मैं यह बतला रहा हूं कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि ये जो घटनाएं हुई हैं और आपकी इन बातों के कारण यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेज़ोल्यूशन पास कर दिया, पाकिस्तान ने पास कर दिया। दूसरों ने कर दिया। अपने देश में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, इस देश को बदनाम मत कीजिए और इस देश को बदनाम करके अल्पसंख्यकों के प्रति ऐसा वातावरण मत बनाएं जो कि सच्चाई नहीं है। मिथ्या प्रचार मत कीजिए।

सभापति महोदय, इसके बाद एक ज़िक्र किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एच० हनुमनतप्पा: मल्होत्रा जी, एक मिनट।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, बाद में आपको भी मौका मिलेगा।

श्री एच० हनुमनतप्पा: आपने कह दिया, आपने क्या किया कि फॉरेन जर्नलिस्ट के ओपीनियन को पार्लियामेंट में डाल दिया। Was it necessary? ...*(Interruptions)*...It may not be a point of order, Mr. Chairman, but a point of propriety. ...*(Interruptions)*...Was it necessary to have brought it on the record? ...*(Interruptions)*....

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, मैंने उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का ज़िक्र किया। मेरे दोस्त पूछ सकते हैं कि गुजरात के बारे में आप कह सकते हैं। गुजरात के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि मैं अपना मत बिल्कुल प्रकट नहीं करूंगा, केवल जो टिप्पणियां हैं, वही प्रस्तुत कर रहा हूं। Two oldest living Gandhians, Chelubhai Naik and Chunilal Jaiswal. ...*(Interruptions)*....

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): खुराना जी वाली बात तो बोलिए।

श्री टी०एन० चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): वे दूसरे हाऊस के मैम्बर हैं, चेयरमैन साहब इजाज़त नहीं देंगे उनका नाम लेने के लिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: चेलुभाई नायक और चूनी लाल दोनों की आयु 82 साल है और दोनों केवल गांधियन नहीं हैं, महात्मा गांधी जी ने उनको वहां आदिवासियों में काम करने के लिए भेजा था, वे आज तक काम कर रहे हैं पिछले 50 साल से और उन्होंने ऐफिडेविट पर, शपथ-पत्र देकर माइनॉरिटी कमीशन के सामने जो अपना मेमोरेंडम दिया, मैं उसकी केवल 5-6 लाइनें पढ़ रहा हूं:— That the Dangs incident is not to be perceived as an attack on Christians: that it is a long simmering reaction to the conversions by the Christian Missionaries; that the Missionaries have used and even now use unethical means to convert; and, that this is not the beginning, but the Culmination.

श्री सनातन बिसि: चेयरमैन साहब, पैरा 8 बोला गया है। ...**(व्यवधान)**...The President has

expressed anguish over the recent incidents in Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa... ...*(Interruptions)*. But they are justifying it!

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am talking of Gujarat. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Mr. Bisi, when you get time, you can reply to him. ...*(Interruptions)*...

MISS SAROJ KHAPARDE: Is that a copy of the memorandum or a newspaper? ...*(Interruptions)*...

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: मैं पेपर में से पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री सभापति: आप कहां से पढ़कर बता रहे हैं?

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: यह पेपर के अंदर छपा है, उसको क्वोट किया गया है इसके अंदर, उसको पढ़कर बता रहा हूं।

श्री सभापति: किस चीज का क्वोट है?

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने उसकी फोटोस्टेट कापी करवाई है, यह "पोलिटिकल आब्ज़र्वर" में से है।

श्री सभापति: वे कह रहे हैं कि यह "पोलिटिकल आब्ज़र्वर" में से है।

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: That the Missionaries have been inciting conversions; that the Missionaries have used and even now use unethical means to convert; that this is not the beginning, but the culmination; that the missionaries have been inciting the converted tribals into vandalism; that the Missionary schools have punished students who have worn Gandhi caps during the last five years; that nearly two dozen idols of Shiva and Hanuman, revered by the tribals have been desecrated and broken.

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी: मान्यवर, यह जो पढ़ रहे हैं यह मेमोरेंडम नहीं है, यह आर॰एस॰एस॰ का जो मेमोरेंडम है ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: क्या पढ़ रहे हैं?

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी: यह बी॰जे॰पी॰ टूडे और आर॰ एस॰ एस॰ टूडे से पढ़ रहे हैं, यह मेमोरेंडम से बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने ....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: कितनी बार पढ़ोगे मल्होत्रा जी आप?

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने 1935 में "हरिजन" में 11 मई को यह बात कही कि—"अगर मेरे हाथ में सत्ता हो और मैं कानून बना सकूं तो मैं धर्मांतरण का सारा कारोबार ही बंद करा दूं। इससे वर्ग-वर्ग के बीच" ....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: गांधी जी का पढ़ रहे हैं ....**(व्यवधान)**

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी: यह आर॰एस॰एस॰ टुडे में जो क्वोट किया गया है वह पढ़ रहे है ....**(व्यवधान)** He is quoting wrongly. ....*(Interruptions)*....

श्री सभापति: यह गांधी जी ने नहीं कहा है ....**(व्यवधान)**

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: आप इसे कहिए कि गलत है। अगर गलत है तो बता दीजिए मैं पढ़ रहा हूं 11 मई, 1935 को गांधी जी ने "हरिजन" में जो लिखा है ....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: मल्होत्रा जी, कितना पढ़ोगे? विश्व हिंदू परिषद, आर॰एस॰एस॰ टुडे, हाऊ मैनी थिंग्ज़ ....**(व्यवधान)**

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, a number of times the Chair has ruled that when a Member is speaking the other Members should not interrupt unless the concerned Member yields. But, what we have seen is that some senior Members and even those Members who are on the panel of Vice-Chairmen are continuously standing up and making a running commentary. ....*(Interruptions)*....

MISS SAROJ KHAPARDE: We have every right. ....*(Interruptions)*....

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Then we have also got the same thing. ....*(Interruptions)*....

MISS SAROJ KHAPARDE: I have got every right to speak if somebody is quoting my party wrongly. ....*(Interruptions)*....

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I have no way to define if the Member who is on the panel of Vice-Chairmen says, "This is my right." Is this the way to run the House? I am very sorry. ....*(Interruptions)*.... What is this going on? ...Why are they so scared? ....*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: If the hon. Member feels that he is wrongly quoting Gandhiji, please bring it to me. We shall see it afterwards.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: That is all, Sir. ....*(Interruptions)*....

श्री सभापतिः आपने कहा ना कि वह गलत क्वोट कर रहे हैं ....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डेः मैंने वह नहीं कहा। सर, मैंने यह कहा कि कितनी बार बाहर के, विदेश के पेपर से पढ़ोगे? मैंने यह कहा और मैंने बार-बार मैगजीन का नाम पूछा, और मैंने कुछ नहीं पूछा। क्या यह भी मुझे अधिकार नहीं है।

श्री सभापतिः वह तो उन्होंने बता दिया आपको। वह बात खत्म हो गई।

कुमारी सरोज खापर्डेः ठीक है, बात खत्म हो गई। मैंने जो पूछा है, इसीलिए पूछा है कि कहां से क्वोट कर रहे हैं?

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः यह मैंने कहा है। महोदय, 11 मई, 1935 को "हरिजन" में उन्होंने यह बात कही है। मैं पूरा पढ़ देता हूं....**(व्यवधान)**

श्री एच॰ हनुमनतप्पाः आपने वेंकैया नायडू को यील्ड किया, मुझे यील्ड नहीं कर रहे हैं एक मिनट के लिए।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः सभापति महोदय, इससे मेरा बीच में तारतम्य टूट जाता है।

श्री एच॰ हनुमनतप्पाः बी॰जे॰पी॰ के लिए यील्ड करने से तारतम्य नहीं टूटता है, कांग्रेस के लिए यील्ड करने से तारतम्य टूट जाता है।

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः नहीं, वह प्वाइंट आफ आर्डर था। अगर कोई प्वाइंट आफ आर्डर है, तो आप बता दीजिए।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, we are discussing the Motion of Thanks on the President's Address. The President in his Address has expressed regred on the incidents which occurred in the country. Can a Member who is moving the Motion of Thanks on the President's Address deviate from the view or opinion expressed by the President? ....*(Interruptions)*....

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: I am not deviating from that. ....*(Interruptions)*.... I am not yielding. ....*(Interruptions)*....

SHRI H. HANUMANTHAPPA: The President has expressed regret on the atrocities on minorities. ....*(Interruptions)*.... Now the hon. Member is justifying it by quoting what the foreign journalists have written. ....*(Interruptions)*.... Is it on the lines of the Motion of Thanks? ....*(Interruptions)*....

SOME HON. MEMBERS: Not at all ....*(Interruptions)*....

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्राः सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसी भी अल्पसंख्यक पर होने वाले अत्याचार पर चिंता प्रकट की गई है और मैंने स्वयं कहा है कि किसी भी अल्पसंख्यक पर अन्याय या अत्याचार होना इस देश के लिए कलंक है....**(व्यवधान)** क्या बता हो गई ....**(व्यवधान)** The moment I start speaking, ...*(Interruptions)*....

कुमारी सरोज खापर्डेः आपने यहां पर जो क्वोट किया मल्होत्रा जी, अपोजीशन वालों ने आपके बारे में आपत्ति तब उठाई जब ....**(व्यवधान)**

श्री सभापतिः बात खत्म हो गई ना....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डेः आप तोड़-मरोड़कर सारा मसला सदन के सामने रखते हैं और हम कुछ स्पष्टीकरण भी नहीं कर सकते?

श्री सभापतिः नहीं बात खत्म हो गई। उन्होंने जो जवाब दिया, उसके साथ आपकी बात खत्म हो गई।

कुमारी सरोज खापर्डे: अभी इन्होंने जो कहा, मैं उस पर कुछ कह रही हूं। हमने आपत्ति तब उठाई जब आपने बी०जे०पी० के एक वर्तमान पत्र में जो छपा हुआ विदेशी का इंटरव्यू था, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया ....**(व्यवधान)**

श्री सभापति: वह बात तो खत्म हो गई ना, उन्होंने बता दिया। ....**(व्यवधान)**

MISS SAROJ KHAPARDE: He is again raising that issue.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: राष्ट्रपति जी ने यह बात कही कि ये 3 घटनाएं बहुत निंदनीय हैं, उनकी जांच हो रही है। मैंने भी यही बात कही। परन्तु उन्होंने कहा कि इसको अपवाद बनाइए। यह अपवाद है, यह एबेंशंस हैं, यह कोई सारी मायनोरिटी पर हमला हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, यहूदियों की तरह के अत्याचार हो रहे हैं इस तरह का झूठा मिथ्या आरोप मत कीजिए और इस तरह के प्रचार के कारण सारी दुनिया में हिन्दुस्तान का नाम बदनाम मत कीजिए। ....**(व्यवधान)** हो तो यह रहा है, कहा यह जा रहा है कि ....**(व्यवधान)** और इसके लिए यह कहा जा रहा है कि जैसे धर्मान्तरण बहुत अच्छी बात है। अगर धर्मान्तरण ठीक है तो पुनःधर्मान्तरण भी ठीक है। अगर धर्मान्तरण होने में महात्मा गांधी जी ने जो कुछ कहा है मैं उसको कोट करता हूं तो आप गांधी जी का नाम सुनना नहीं चाहते। ....**(व्यवधान)** धर्मान्तरण के बारे में मैं उसका उल्लेख करता हूं तो आप इस तरह से हल्ला करते हैं। ....**(व्यवधान)** मुझे मालूम है कि आज आप गांधी जी से प्रेरणा नहीं लेते, आज आप गांधी जी को अपना नेता नहीं मानते, आज आपकी नेता सोनिया गांधी हैं, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं कि गांधी जी का नाम भी सुनना आपको पसंद नहीं, गांधी जी की कोटेशन सुनना पसंद नहीं करते।

श्री ब्रतीन सेनगुप्त (पश्चिमी बंगाल): गांधी जी की हत्या किसने की थी?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय ....**(व्यवधान)**

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी: गांधी जी का मर्डर किसने किया? Who has murdered Gandhiji? Who was behind the assassination of Gandhiji?

PROF. VIJAY KUAMR MALHOTRA: You people have murdered Gandhiji's soul.

राष्ट्रपति जी ने इसका जिक्र किया है कि 1998 में साम्प्रदायिक हत्याओं में, वैसे तो एक व्यक्ति की भी हत्या हो तो बहुत बुरी बात है, परन्तु 1996 में 712, 1997 में 734, 1998 में साम्प्रदायिक दंगों में मरने वालों की संख्या 473 रही। यह 473 की संख्या भी रुकनी चाहिए। परन्तु कांग्रेस के जमाने में दूसरी पार्टियों के जमाने में जितनी हत्याएं हुई उससे कम हत्याएं इन 10 महीनों में हुई है और इस तरह का वातावरण मत बनाइए कि सारी दुनिया के अंदर यह मैसेज जाए कि हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और अल्पसंख्यकों के बारे में इस प्रकार की राय बनाएं इसलिए मैंने यह कोटेशन आपके सामने पढ़ी थी।

सभापति महोदय, यहां पर यह कहा जा रहा है कि सरकार चल नहीं रही है और यह बात बड़े जोर से प्रचारित की जा रही है कि सरकार चल नहीं रही है। प्रतिदिन सरकार पर संकट आता है। जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ तो कुछ लोगों ने इस बात की टिप्पणी की और यह कहा कि इतना लम्बा भाषण क्यों दिया गया। आप कह रहे हैं कि वह टार्चर था। जब उपलब्धियां इतनी ज्यादा हों और उनको संक्षेप में भी बताना हो तो भी इतने अधिक समय में इतनी बातें कहनी पड़ती हैं। 60 पोइंट लिखे हैं। मैं दावे से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या जनता दल की सरकार या यूनाइटेड फ्रंट की सरकारों ने 50 सालों में जो उपलब्धियां नहीं की वह वाजपेयी सरकार ने 10 महीने में उपलब्धियां की हैं। ....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: मल्होत्रा जी, 10 महीनों की उपलब्धियों के कारण उस दिन सेंट्रल हाल में बिल्ली भी रोयी थी। आपका 10 महीने का सारा अनुभव सुनकर बिल्ली भी रो रही थी उस दिन सेंट्रल हाल में।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, यह बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या बात है।

श्री सभापति: आप बोलिए, अपनी बात कहिए।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: सभापति महोदय, पिछली जितनी भी सरकारें रहीं सब के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, प्रधान मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर मुकदमे चले परन्तु भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने में किसी मंत्री पर एक आरोप नहीं, एक केस नहीं, इस प्रकार कोई मुकदमा नहीं। टोटल स्केम फ्री, टोटल घोटालों से मुक्त यह सरकार चल रही है।....**(व्यवधान)**

डा० वाई० लक्ष्मी प्रसादः यूनाइटेड फ्रंट के कंवीनर कहां है?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्राः जो अणु विस्फोट हुआ पोखरण में, उस अणु विस्फोट से सरकार ने देश को विश्व के पहले छः देशों में लाकर के खड़ा किया है। मैं उसका अधिक उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कहा जा रहा है। आज हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार 27 बिलियन डालर तक पहुंचा है। यह आज तक का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार है। पिछले 10 महीनों में रुपए की कीमत डालर के मुकाबले में कम नहीं हुई। हम अभी पाकिस्तान गए थे वहां पर पिछले कुछ दिनों के अंदर हालात इतने खराब हो गए थे। हमें लिखित में दिया गया था कि आफिशियली एक डालर में हमारी कीमत 46 रुपए है परन्तु बाजार में, बैंक में 52 रुपए मिलेंगे और कुछ दिन पूर्व बाहर 65 रुपए तक मिलते थे। हमारी मुद्रा स्थिर है, हमारी आर्थिक स्थिति स्थिर है। पोखरण कांड के बाद हिन्दुस्तान पर जो पाबंदियां लगाई गई उन पाबंदियों को हमने झेला है सरकार ने आर्थिक दृष्टि से देश को स्थिर रखा है। यहां पर जो ....**(व्यवधान)**

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार): गरीबों को खाने को नहीं दे रहे हैं। ....**(व्यवधान)**

1.00 P.M.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्राः थोड़ा सा अगर आपके पास समय हो तो राष्ट्रपति भाषण को आप पढ़ लें। नई आवास नीति बनाना, बेरोज़गारी दूर करना, 9वीं पंचवर्षीय योजना को लागू करना, प्रति वर्ष 20 लाख मकान बनाना, किसानों के लिए नई योजना बनाना, भारतीय मूल के विदेशियों को पी०आई०एल० के कार्ड देना, पचासों मुद्दे हैं जिनका राष्ट्रपति भाषण में उल्लेख किया है। ये काम पचास साल में आपने नहीं किया।

श्री सभापतिः मल्होत्रा जी, देखिए, एक बज गया है।

PROF. VIJAY KUAMR MALHOTRA: Only five minutes more, Sir.

श्री सभापतिः पांच मिनट में खत्म कर लेंगे? We will sit for five minutes more.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्राः नई योजनाएं युवकों के लिए महिलाओं के लिए बच्चों के लिए खिलाड़ियों के लिए बनाई गई हैं, उन सब योजनाओं का इसमें उल्लेख है। ....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डेः एक महिला मुख्य मंत्री थी, पिछड़े वर्ग की थी उसको तो हटा दिया। अब महिलाओं के बारे में क्या बात कर रहे हैं?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्राः नई राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई है, नई दूरसंचार नीति बनाई है। जितने भी विभाग हैं, उनकी नई नीतियां बनाई हैं।

सभापति महोदय, मैं इसमें सिर्फ एक बात का उल्लेख और करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने जो सिलचर से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़कों का एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई है जिसके अंदर लाखों लोगों को नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को काम मिलेगा जब ये सड़कें छः-छः लेनों की बनाई जाएंगी। सारे एयरपोर्ट्स को नए सिरे से बनाया जाएगा, उनके निगम बना दिए गए हैं। जितने बंदरगाह हैं, उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं के प्रतिफल बहुत शीघ्र सामने आने वाले हैं। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि यह सरकार राष्ट्रीय एजेंडे के मुताबिक काम कर रही है। सभापति महोदय, यह ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अलग था और राष्ट्रीय एजेंडा अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रखा था परंतु यह मिली-जुली सरकार है। यह भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार होती और उसका ....**(व्यवधान)**

भाजपा की सरकार होती और हमें दो-तिहाई बहुमत होता तो हमारा एजेंडा अलग हो सकता था परंतु अब हमारी सरकार का राष्ट्रीय एजेंडा है और राष्ट्रीय एजेंडा को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय एजेंडा के अंदर सभी सहयोगी पार्टियों का पूरा मन्तव्य है। उसी के मुताबिक काम किया जा रहा है। बार-बार दूसरी बातें की जा रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके प्रधान ने तथा इनके प्रवक्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया और कहा कि बिहार के अंदर हमने अपनी राय में परिवर्तन इसलिए किया कि हम वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राज नहीं चाहते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है। सरकार को संघ नहीं चला रहा है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ...**(व्यवधान)**... पिछले पचास साल में कांग्रेस की सरकारें रहीं केन्द्र में व अनेक प्रदेशों में जनता देल व संयुक्त मोर्चे की सरकारें थीं और हैं। क्या हिन्दुस्तान में एक भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति पर कभी हिंसा का कोई केस बना? कभी कोई

साम्प्रायिकता का केस बना है? कभी किसी स्वयंसेवक पर एक भी केस में किसी एक को भी सजा हुई है? आपकी सरकारों ने किसी को पकड़ कर बंद किया तो उसका नाम बताइए। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केवल तीन बातों के लिए अपना अभियान चलाया, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और उसके साथ चरित्र-निर्माण। उनके ऊपर मिथ्यारोपण करके, उनका नाम ले करके, बहाना बना करके राजनीति खेलने का कोई कारण नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ...(व्यवधा-न)...

श्री बालकवि बैरागी (मध्यप्रदेश): सभापति जी, ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं या आर०एस०एस० की तरफ से बोल रहे हैं, ज़रा पूछ लीजिएगा इनसे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: आपने जो कहा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि यह सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुताबिक नहीं चल रही है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप उनके नाम का मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे: राज्यपाल क्यों आर०एस०एस० का बिहार में रखा है? महिलाओं की सुरक्षा करना ....महिला मुख्य मंत्री को क्यों हटा दिया?

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: वह तो आप हटा रही है। आपने तय कर लिया राबड़ी देवी जी को हटाने का।

श्रीमती सरोज दुबे: सभापति महोदय, इन्होंने पहले देश को हिन्दू और मुसलमान में बांटा, अब इस देश को हिन्दू और ईसाई में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस का सहयोग लेकर आप राबड़ी देवी जी को हटाने वाली हैं, क्यों हमसे कह रही हैं? कांग्रेस का सहयोग इसी शर्त पर ले रही है। हमसे क्यों महिला की बात कर रही है?

सभापति महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया की बड़ी-बड़ी शक्तियां हिन्दुस्तान को अस्थिर करना चाहती है। वाजपेयी सरकार को हटाना चाहती है, देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करना चाहती हैं। आप जाने-अनजाने उसके सहभागी मत बनिए। इस देश को, इस सरकार को चलने दीजिए। वाजपेयी जी की सरकार की दस महीने की उपब्धियों के बाद यदि सरकार को आने वाले चार वर्ष मिल जाएं तो यह देश अपने परम वैभव पर पहुंचेगा। मैं आशा करता हूं कि आप राष्ट्रीपति जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 2.05 P.M.

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eleven minutes past two of the clock,

[The Vice-Chairman (Shri Sanatan Bisi) in the Chair.]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Motion of Thanks on the President's Address. Sardar Balwinder Singh Bhundar to second the Motion.

SHRI BALKAVI BAIRAGI : Sir, no Minister is there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI: Is there no Minister? When there is no Minister.....

SHRI MD. SALIM : This is serious.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) : Just a minute.

I adjourn the House for ten minutes.

The House then adjourned at twelve minues past two of the clock.

The House reassembled at twenty minutes past two of the clock, —**The Vice-Chairman (Shri Sanatan Bisi)** in the Chair.

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI P.R. KUMARAMANGALAM): Sir, with the permission of the Chair, may I, at first, apologise to the Chair and the House for no Cabinet Minister being present earlier. My colleague, Satyanarayan Jatiyaji got hels up in the traffic. I am sure this will not happen again.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): It should not happen again.

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Yes, Sir. I assure you on that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Sardar Balwinder Singh Bhundar to second the Motion of thanks on the President's Address.

MOTION OF THANKS OF THE PRESIDENT'S ADDRESS (Contd.)

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर (पंजाब): आदर-णीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण पर श्री मल्होत्रा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारा देश वख-वख धर्मों वे जातियों का देश है। हमें मिल-जुलकर देश को आगे ले जाना है और मूझे खूशी है कि पिछले 50 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है और हम कई क्षेत्रों में दुनिया के मुकाबले में आ गए हैं। प्रेजीडेंट साहब ने जो एडरेस पेश किया है उसके वख-वख पैरों में देश की तरक्की की बात की है यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं सारी बातों को एकदम स्टार्ट नहीं करुंगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए मैं एग्रीकल्चर, जो पेज 15 पर और 17 नंबर पैरे पर स्टार्ट होता है वहां से कहना शुरु करता हूं। माननीय उप-सभाध्यक्ष जी हमारे देश ने पिछले 50 वर्षों में 30 इस क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। हिन्दुस्तान एक खेती प्रधान देश है और इसकी आर्थिकता खेती पर निर्भर करती है, ऐसा कहना कोई अनोखी बात नहीं होगी क्योंकि हम अभी तक अपने इण्डस्ट्रियल सेक्टरों में इतनी तरक्की नहीं कर सके कि दुनिया के मुकाबले में आ सकें। कुछ क्षेत्र तो उनमें है लेकिन खेती में हमें गर्व हैं और हम गौरव से कह सकते हैं कि जो सबसे उत्तम चीज है वह अनाज है, उसके बाद दूसरी उत्तम चीज दूध है। अनाज में भी हमारा गेहूं है और राइस, गन्ना है। गेहूं में हम तीन बड़े देशों में आगे है, शुगरकेन में भी हम दूनिया के मुकाबले में आगे है, राइस में भी हमारी पैदावार काफी और बहुत ज्यादा है। हम दुनिया के मुकाबले में पहुंच चुके हैं, यह हमारे लिए सबसे अधिक गौरव की बात है। दूध का क्षेत्र सबसे अच्छा है। हिन्दुस्तानी लोगों के लिए यह वेष्णो देश है इसलिए दूध के क्षेत्र में हम दुनिया में एक नम्बर पर आ गए हैं। जहां तक देश की तरक्की का, देश की पॉलिसियों का संबंध है वहां देश के किसानों, खेती की पैदावार करने वाले किसानों को शाबासी जाती है और मैं उनको शाबासी देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सारे हाउस वाले हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि देश की असली प्रॉब्लम गरीबी दूर हो। गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार पैदा करना होगा। गरीबी दूर करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, खेती ही हमारे देश का प्रमुख स्रोत है और उसमें हम आज बहुत आगे बढ़ गए हैं लेकिन मैं साथ ही साथ कुछ सजेशन भी देना चाहता हूं कि जितनी देर हम इसमें और तरक्की नहीं करेंगे, इसके वीक पाइंटस को कवर नहीं करेंगे तब तक हमारे आगे बढ़ने के लिए स्कोप नहीं होगा। जैसा हमने फूड ग्रेन में बताया, मिल्क फूड में बताया है वही वेजिटेबिल अरो फ्रूट्स में भी हम दुनिया के मुकाबले में आ गए है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए।]

सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कभी-कभी सब्जियों की शर्टेज हो जाती है, फ्रूट्स की महंगाई बहुत ऊपर चली जाती है। ये फिगर्स वृर्टीकचर में हमारी स्थिति को बतराती है। India produces around 48 million tonnes of fruits and 68 million tonnes of vegetable every year. यह फिर बताती है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा फ्रूट और वेजीटेबल पैदा करने वाले देशों के मुकाबले में पैदावार कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी कमजोरियां हैं उनको हमें नोट करना चाहिए और उनको दूर करने के लिए हमको यत्न करना चाहिए। फूड ग्रेन का जो वेस्टेज है, उसको हैंडलिंग वगैरह करने में, स्टोरेज में, यह वेस्टेज बहुत ज्यादा है। हैंडलिंग में ही यह वेस्टेज 5 से 10 परसेंट है और स्टोरेज में भी तकरीबन इतना ही है। इसी तरह से जो वेजीटेबल और फ्रूट्स में 30 से 40 परसेंट वेस्टेज है। इसलिए हम जनता की तरक्की के लिए सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अगर उनका जो यह लास है, अकेले वेजीटेबल और फ्रूट में, जो यह 30 से 40 परसेंट लास है, इसको हम अगर जोड़े तो इसमें अकेले 50 हजार करोड़ रुपए का लास होता है। एक साल में हार्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स में इतना लास हो जाता है। इसलिए अगर हम सि वेस्टेज को, इस लास को रोक लें तो हम दुनिया में नंबर एक पोजीशन पर आ सकते हैं। इसी तरह से हम अगर फूड ग्रेन का लास रोक लें तो हम इसको एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं। बाकी जो हमारी प्राबलम, जो कभी ओनियन के बारे में हो जाती है, कभी पोटाटो की हो जाती है, कभी किसी वेजिटेबल के बारे में हो जाती हैं वह नहीं होगी। आज से आठ-दस साल पहले एक समय हम व्हीट बाहर से मंगाते थे, शुगर बाहर से मंगाते थे, आयल सीड्स बाहर से मंगाते थे, लेकिन आज

हालात बदल गए हैं। ये सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। आज हर फील्ड में हमारा किसान आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसका जो वीक प्वाइंट है उसको कवर करने की जरूरत है। इसके लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं।

जनरली हमारे देश में पैदावार में बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन इसको कवर करने के लिए हमें चाहिए कि जो पैरिसेबल क्राप है, जिसमें वेजीटेबल और हार्टिकल्चर आता है, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज, फार्म सेक्टर से स्टार्ट करके मार्केट सेक्टर तक हमें बनाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते है तो इससे कन्ट्री का बहुत बड़ा भला होगा। इससे जहां किसान को फायदा होगा, वहां इससे देश को भी फायदा होगा, राज्य सरकारों को भी इससे फायदा होगा और इस क्षेत्र में हम दुनिया में मुकाबले पर आ जायेंगे। इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके लिए सिर्फ अरेंजमेंट करने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस प्वाइंट को नोट करेगी और इसमें पूरा इंटरेस्ट लेकर कोल्ड स्टोरिजिस की चेन बनाएगी।

इसी तरह से फूड ग्रेन का वेस्टेज रोकने के लिए जो स्वाइलो सिस्टम है, इसके लिए इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसकी ड्यूटी कम करनी चाहिए, ताकि जो फूड ग्रेन का वेस्टेज होता है, वह न हो सके। इसके लिए मशीनरी बाहर से मंगानी पड़ती है। इसके लिए सब्सिडी भी सरकार को स्टेट्स को देनी चाहिये। इसको, अगर इंडिविजुअल, गांव वाले चाहते हैं तो उनको भी देनी चाहिये और स्टोरेज बड़े पैमाने पर बनाने चाहिये। गांव-गांव में स्टोर लगनी चाहिये। इससे आपका वेस्टेज कम होगा और स्टोरेज में जो डिस्टब होता है वह भी कम हो और देश को अधिक अनाज मिले। किसान भी चाहता है कि उसे अच्छी कीमत मिले इसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि उसकी जो पैदावर हो उसको उसका अच्छा कीमत मिल सके, वह उसको अच्छे दामों में बेच सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस चीज की तरफ भी जोर से ध्यान देना चाहिये।

इसी तरह मैं तीन-चार और सुझाव देना चाहता हूं। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि सरकार शायद खेती की उपज पर भी टैक्स लागाने जा रही है। मैं बहुत जोरों के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि उसको यह देखना चाहिये कि किसानों की हालत पहले ही खराब है और वह सुईसाइड कर रहे हैं। उसकी पैदावार भी बढ़ रही है और देश का उसने बहुत भला किया है। लेकिन देश के कंस्जयूमर खाने की चीजों की कीमत बढ़ने पर रोते हैं और प्रोड्यूसर भी रोते हैं कि उसको उसकी पैदावार का ठीक मूल्य नहीं मिलता। स्टडी भी बताती है कि इंडिया में जो प्राइस रेट है उसके मुताबिक हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हम प्रोड्यूसर को ठीक बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। न मजदूर को फायदा है और न जिनके खेत हैं उसको फायदा होता है। 31 आइटम ऐसी है जिन्हें माइनस प्राइससे के नीचे बेचना पड़ता है। इसलिए किसान को नुकसान होता है। मैं सरकार को नोट कराना चाहता हूं कि वह देखे कि खेत सेक्टर पर विचार करते समय इस सुझावों पर ध्यान दें। जो पढ़े-लिखे लोग सुझाव देते हैं उनके सुझावों पर अमल करके आप कुछ गलत न कर बैठें। खेती पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। पहले ही यहां बहुत ज्यादा टैक्स है।

श्री रमाशंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): आप यह कहिये कि इसको राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जोड़ा जाए।

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: मैं सुझाव दे रहा हूं। जहां हम धन्यवाद करते हैं, वहां पर सुझाव देना भी हमारा फर्ज है। इसलिए मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि हमारी जो एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री है, इसको ज्यादा इनकरेज करना चाहिये ताकि हमारे किसानों को अच्छी कीमतें मिलें और पैदावर का बढ़ावा हो और दुनिया में हम इस फील्ड में एक्सपोर्ट करने वाले बनें। अभी तीन चार साल से इस फील्ड में यह चल रहा है कि हम व्हीट में सरप्लस हैं, राइस में सरप्लस हैं, और भी चीजें हैं ताकि देश में ज्यादा कमाई हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा सुझाव देना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है। यूरिया की कीमतें बढ़ाई गई हैं। वाइसचेयरमैन साहब को भी मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। यूरिया की कीमतें किसानों के लिए बढ़ाई गई हैं, 4000 रुपये प्रति टन किया है। इससे सरकार को पांच-छः सौ करोड़ रुपये मिलेंगे। इतने पैसे से सरकार का तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन किसान के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि डब्ल्यू०टी०ओ० की स्टडी है, उसके मुताबिक किसी भी सबसिडी के मामले में इण्डिया कहीं भी वर्ल्ड में कम्पीट नहीं करता बल्कि यहां का जो किसान है, वह घाटे में जा रहा है। इसलिए जो यूरिया की प्राइस बढ़ाई गई है, अगर उसको आप वापिस ले लें तो बहुत अच्छी बात है, किसान भी खुशी मनाएगा और सरकार को भी क्रेडिट जाएगा लेकिन आप यह कह सकते हैं कि सबसिडी से हमारे बजट पर बोझ बढ़ रहा है, हम पहले ही घाटे में जा रहे हैं। इसलिए हम यह सुझाव देना चाहेंगे कि अगर सबसिडी को कहीं रोकना है

उसमें यह बात सच है कि आप यह सबसिडी किसानों को नहीं दे रहे हैं। यह जो 9000 करोड़ रुपये की सबसिडी प्रति साल आप दे रहे हैं, यह किसानों को नहीं जा रही है, यह तो इंडस्ट्री वालों को जा रही है। हमारे यहां पर यूरिया पैदा करने वाली लगभग 33 फैक्टरियां हैं। यहां पर यूरिया पैदा करने की लागत 8000 रुपये से 11000 रुपये प्रति टन आती है। इंटरनेशनल मार्किट में यूरिया का रेट 6000 रुपये प्रति टन है और किसान को 3700 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये टन कर दिया है अर्थात् दो सौ रुपया फारमर पर बढ़ाया है और इंटरनेशनल मार्किट में 6000 प्रति टन यूरिया का रेट है और यहान की इंडस्ट्री जो यूरिया पैदा कर रही है वह 8000 से 11000 रुपय प्रति टन कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या जरूरत है इतना महंगा यूरिया पैदा करने की ? जब वर्ल्ड में अवेलेबल है तो जो इंडस्ट्री लास में जाती है, उसको रहने दो। हमारे पास रा मैटिरियल भी उतना नहीं है। रा मैटिरियल भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसलिए हम सुझाव देंगे कि जो इंडस्ट्री वालों को आप सबसिडी दे रहे हैं, उसमें रेशनेल होना चाहिये। यहां की प्रोडक्शन कास्ट 8 से 11 हजार तक आती है, इसलिए इसको 8 हजार तक रोक देना चाहिये। इससे तीन हजार रुपये पर टन इंडस्ट्री वाला ले जाता है और सरकार के खज़ाने पर भी इसका बोझ पड़ता है और किसान के माथे पर यह लाया जाता है कि यह सबसिडी किसान को दी गई है। असल में किसान को यह सबसिडी नहीं दी जाती है, यह सबसिडी इंडस्ट्री वालों को है। इसलिए वाइसचेयरमैन साहब, मैं आपके ज़रिये सरकार को यह कहना चाहता हूं कि जहां यह अच्छे काम किये जा रहे हैं, इन्श्योरेंस वगैरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं, कैश क्रेडिट स्कीम किसान को दी जा रही है, दूसरे सेक्टर्ज़ में भी किसानों को पिछले दो सालों से अच्छी प्राइसेज़ देने लगे हैं, वहां यह सबसिडी बंद कर के किसान को पहले की तरह मैं तो कहता हूं कि कम करनी चाहिये नहीं तो जैसे पहले थी उतनी रहनी चाहिये। यह मेरी ज़ोरदार सिफारिश है किसानों के लिए।

अब मैं दूध सेक्टर के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। दूध के उत्पादन के मामले में हम दुनियां में एक नम्बर पर आ गये हैं। दूध से लोगों को बड़ा काम मिलता है। इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिये ताकि बेरोज़गारी खत्म हो। आप जानते ही हैं कि लैंड-होल्डिंग कम हो रही है। इसलिए ग्रेन के उत्पादन में भी किसान फायदे में नहीं आएगा इसलिए दूध के उत्पादन पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। दूध की मार्किट वर्ल्ड में बहुत है। एम०एम०पी०ओ० को खत्म करना चाहिये, यह भी मेरा सुझाव है। हम इस फील्ड में और तरक्की करें। देश की ज्यादा पापुलेशन खेती पर निर्भर करती है, इससे उनको काम भी मिले और मुनाफा भी मिले और सरकार को अच्छी शाबाशी भी मिले। इसलिए मैं सरकार की उपलब्धियों के लिए उसको धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ सुझाव भी देना चाहता हूं। आम तौर से इस मौके पर सरकार की उपलब्धियां बताई जाती हैं लेकिन मैं साथ-साथ सुझाव भी दे रहा हूं, पता नहीं कैसा महसूस किया जा रहा है लेकिन मैंने सोचा कि मैं यह जरुर कहूंगा कि सरकार अच्छा काम कर रही है और सुझाव देना भी कोई बुरी बात नहीं है।

इसके साथ ही जो नैक्स्ट पैरा है, जो पेज 2 पर पैरा 4 है, और पेज 12 पर पैरा 48 है तथा पेज 16 पर पैरा 48(ए) है, मैं इन दोनों को साथ लेकर सरकार की जो सब से बड़ी उपलब्धि है उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, हमने बड़े क्षेत्रों में बड़ी तरक्की की है, लेकिन फिर भी कई बार बाहर से हमें छोटी-छोटी बातों से थ्रेट आते रहते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पिछले समय में 1972 में हमने सब से पहला पोखरन का एक्सपेरीमेंट किया था। उसके बाद 20-25 साल हम चुप रहे, हालांकि हमारे पास सब कुछ मौजूद था। हम सोचते रहे कि हम अमन चाहते हैं, इसलिए ऐसी कोई घटना न करें। लेकिन अब हमने जो सब से अच्छा काम किया और इसके लिए जो समय चुना, इस पोखरन टैस्ट को करने का जो हमने समय चुना, वह सब से अच्छा समय था। लेकिन काफी तरफ से इसकी नुक्ताचीनी भी हुई, जो कि नहीं होनी चाहिये थी। हम सब देश को मज़बूत बनाना चाहते हैं। अगर देश में शांति चाहते हैं तो शांति के साथ शक्ति भी चाहिये। शक्ति के बगैर कभी कोई देश शांति नहीं ला सकता। शक्ति भी जरूरी होनी चाहिये। हमारे पंजाबी में कहते हैं, पता नहीं आप कैसे बोलते हैं, कि दुनिया मानती है जोरों को, कोई मानता नहीं कमजोरों को। इसलिए जो हमने किया वह जरूरी था। इसलिए मैं सोचता हूं, पुराने तजुर्बेकार भी यहां बैठे हैं, कि इसकी कहीं भी किन्तु-परन्तु नहीं होनी चाहिये थी। सब को इसकी तारीफ करनी चाहिये थी, लेकिन थोड़ा-बहुत इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। फिर भी हमने यह बहुत अच्छी बात की है। अब उसके बाद कह रहे हैं कि हमने जो टैस्ट किया यह सिर्फ दिखाने के लिए किया। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम शांत हैं। हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते और हमने अपनी पालिसी में पहले ही बोला है कि जिस देश के पास एटमिक पावर

नहीं, हम उस देश पर यह करेंगे ही नहीं, और जिसके पास एटामिक पावर है उससे भी हम पहल नहीं करेंगे। इससे ज्यादा हमारी फराकदिली और साफदिली और क्या हो सकती है? यह दुनिया को हम सब बता रहे हैं कि जो-जो हम कर रहे हैं हमारे देश की शांति कायम रखने के लिए कर रहे हैं, हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार की जितनी भी शलाघा की जाए, थोड़ी है। उसके बाद सरकार मजबूत हुई है और देश का दुनिया में नाम बढ़ा है। जो हमें, इतने बड़े देश को कहते हैं कि इंडिया तो कहीं भी, किसी सैक्टर में, किसी जगह पर नहीं है, तो अब हम दुनिया के जो पांच बड़े शक्तिशाली मुल्क हैं, उनकी कतार में आ खड़े हुएहैं। इसलिए इस पर सरकार की जितनी भी शलाघा की जाए उतनी ही थोड़ी है। इसके साथ ही हम कहेंगे कि यह हमारी सरकार की सब से बड़ी उपलब्धि है, जहां इसके बाद वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म हुआ है वहां हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां भी लगीं, लेकिन सब को हमने क्रास किया है। हमारी इकोनोमी स्टेबल है। ऐसा नहीं कि फारेन कंट्रीज में जैसे कई बार सारी इकोनोमी शैटर हो जाती है। हमारा देश मज़बूत है। हम सब मिल कर इसकी जो आंकड़े है उसको हम पार कर गए हैं। हम उसको क्रास कर गए हैं। जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगी थीं वे अपने आप हटने लग गई हैं। उसका सबूत है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही है। वे कम नहीं हुई हैं। उसका सब से बड़ा सबूत हमारे जो गवांडी देश हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात पिछले 15-20 साल से बेहतर हुए हैं। चाहे वह नेपाल है, चाहे वह भूटान है, चाहे वह बंगलादेश है, चाहे वह श्रीलंका है, चाहे वह हमारा गवांडी पाकिस्तान है। मैं इसकी तारीफ करता हूं और एक पंजाबी होने के नाते जोर से तारीफ करता हूं कि 50 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो यह काम किया है यह सब से अच्छा काम किया है। यह दुनिया में नेक और देश के लिए अच्छा काम किया है। पाकिस्तान के साथ यह जो पहलकदमी की गई है, यह सब से अच्छा काम किया गया है। पाकिस्तान के साथ जो लाल लकीरें खींची गई थीं, जो बदकिस्मती की बात थी, बार-बार हमारी जंगें हुई, बार-बार हमारे दोनों देशों का बड़ा नुकसान हुआ, जहां सम्पत्ति का नुकसान हुआ वहां इंसानों का भी हुआ, और देश की जो इकोनोमी है उसको भी बार-बार बहुत मुश्किलें आई, लेकिन यह काम करने से अब एक नया सवेरा शुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि इससे देश को भी फायदा मिलेगा और दुनिया में भी इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा और प्रधान मंत्री जी, जो आप पहलकदमी करके पाकिस्तान की धरती पर गए और जितना वहां स्वागत किया गया उसका सबूत है कि यह बहुत अच्छी फारेन पालिसी है और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे है और हम यह भी चाहेंगे कि जल्द ही वह दिन आए जब रेल और रोड के साथ ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाए। जो एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट है, वह चालू हो जाए। साथ ही यह एशियन जोन में गल्फ तक पहुंचने के लिए ड्राई एरिया है, हम चाहेंगे कि यह दिनों-दिन अच्छा हो जाए। हम चाहेंगे कि बॉडर पर टेंस के बजाय ट्रक होने चाहिए जहां से कि माल जाए, माल आए और जहां फौजें बंदूकों से भिड़ती है वहां भंगड़े पेने जाएं ताकि हमारा देश खुशी के साथ तरक्की करे हम पंजाब वाले यह सब से पहले चाहते हैं क्योंकि पंजाब ने सारे देश से ज्यादा यह दुख झेला है। बॉर्डर पर जब बम चलते है, टैंक के गोले चलते है तो हमारे बीर जवान ही नुकसान उठाते है और हमारे वीर किसान भी उजड़ते हैं। हमारी धिएं व बहनें उस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होती है। इसलिए हमारी फारेन पॉलिसी में सब से आखिर का जो कमद है, वह काबिले तारीफ है और यह पिछले 50 सालों की दूसरी सब से बड़ी उपलब्धि है। साथ ही चाइना वगैरा के साथ संबंध सुधारने के लिए जो बात हो रही है, मैं उस की भी जोरदार तारीफ करता हूं।

चैयरमैन साहब आज सारी दुनिया एक बन गई है। मैं तो चाहता हूं कि दुनिया में किसी भी देश के पास एटॉनिक आर्म्स नहीं होने चाहिए , सारी दुनिया को एक जैसे चलना चाहिए! यह नहीं कि इंडिया के पास एटॉनिक पावर नहीं होनी चाहिए और सिफर 5-6 देशों के पासी होनी चाहिए। सब देश बराबर के हों। आज हर देश को अमन की ज़रूरत है, हर देश को अपनी सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए सब के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, अकेले किसी भी यह दादागिरी नहीं होनी चाहिए; लेकिन हम यह भी चाहते है कि दुनिया में अमन के लिए एटॉमिक आम्सर खत्म होने चाहिए। यही हमारी सरकार की मंशा है जिस की हमें जोरदार ढंग से तारीफ करनी चाहिए।

चैयरमैन साहब, मैं अब आप का ध्यान पेज नं० 3 के आठवें पैराग्राफ की ओर सींचना चाहता हूं जिस में हमारी सरकार ने वायदा किया है:

> "The Government is firmly committed to uphold secularism."

चैयरमैन साहब, मैं ने सुबह से देखा कि यहां काफी शोर-शराबा हो रहा था। मैं तो चुप बैठा था और सोच

रहा था कि देश में सब लोग अच्छे हो गए है और चाहते हैं कि यहां अमन हो, यहां किसी मायनोरिटी पर हमला न हो और यहां किसी गरीब को मारा न जाए। यह बड़ी अच्छी बात है। यही हम सब का एम होना चाहिए। चैयरमेन साहब, हर पार्टी का मैनीफेस्टो बहुत अच्छा होता है, लोग बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उस पर अमल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सर, इस सरकार को आए अभी एक साल भी नहीं हुआ, सिफर 11 महीने ही कह सकते है, लेकिन इस समय में दो-तीन बातें हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो हुआ, यह अच्छा नहीं हुआ और सरकार ने भी माना है कि बुरा हुआ। इस से हमें, सारे हाउस को और देश को भी दुख है। यह नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने सब से अच्छा काम यह किया कि एकदम उन पर एक्शन लिया। उड़ीसा में इंक्वायरी कमीशन बनाया, गुजरात में पहली दफा हुआ कि इस तरह के केस में प्राइम मिनिस्टर साहब वहां चलकर गए और मध्य प्रदेश में भी इंक्वायरी कमेटी गयी और जोर से एक्सशन लिया ताकि आगे से ऐसी कोई घटना न हो और देश में मायनोरिटीज व वीकर सेक्शन एक साथ प्यार से मिलकर रह सकें। इस कार्य के लिए हम सब को सरकार की तारीफ करनी चाहिए। चैयरमैन साहब, मैं जहां सरकार की तारीफ करता हूं वहीं सरकार को एक बात और कहना चाहता हूं कि आनरेबल प्रेसीडेंट साहब ने इस बारे में जो फिगर्स दिए है, वह बता रहे हैं कि:

> "The Government's record in maintaining peace and communal harmony is shown by the fact that 1998 had the fewest deaths due to communal violence in the last ten years."

यह जो लिखा है है, करेक्ट लिखा है और फिगर्स के बारे में किसी को शक हो तो वह बोल भी सकेगा। इसलिए मैं सरकार की तारीफ करता हूं कि पिछले समय में जो होता आ रहा था, वह जरूर थोड़ा-बहुत हुआ जिस पर हमें बहुत दुख है, लेकिन यह सब से कम हुआ और यह सब पार्टी वालों को चाहिए कि आगे से इस तसरह की घटना एक भी नहीं होनी चाहिए। किसी मां की आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, किसी का बच्चा किसी की गोद से नहीं छिनना चाहिए। इस का केस एक है और उस का एक केस है, यह नहीं होना चाहिए। यह कौनसा धर्म मानता है, वह कौनसा धर्म मानता है, यह नहीं होना चाहिए। इस के लिए मैं गवर्नमेंट की बहुत जोरदार श्लाघा करता हूं और गवर्नमेंट को एक सेजशन भी देना चाहता हूं। चैयरमेन साहब, यह हमारे लिए बदकिस्मती की बात है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, यह मेरी आदत भी नहीं, जो हो गया वह हो गया। लेकिन अगर हम दिल से आगे के लिए इसको रोकना चाहते हैं तो मैं सारे हाऊस से अपील करना चाहता हूं कि इस बारे में एक रेज़ोल्यूशन पास किया जाए। मैं सुबह से सुन रहा था, इधर से भी बोल रहे थे, लेकिन कोई नहीं बोला उस बारे में कोई नहीं बोला जो 1984 में चार हजार इंसानों को बगैर किसी दोष के साड़ा गया, मारा गया। किसी ने अथरू नहीं बहाए, किसी ने इस बारे में पार्लियामेंट में मता नहीं लिया। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐ सरकार वालो, अब मौका है आप यह मता भी हाऊस में लाएं ताकि आगे के कोई ऐसी बात न करे। अभी भी वे लोग फिर रहे है, घूम रहे हैं जिन्होंने सौ-सौ कत्ल किए हैं और उन्होंने बड़े-बड़े ओहदे लिह हुए हैं। मैं किसी का नम लेकर किसी विवाद में नहीं जाना चाहता, यहां जो बैठे हैं में उनमें किसी को दोषी नहीं मानता, दोष करने वाला तो कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया, लेकिन इस बात का दुख है कि यह देश जो आजाद है, उस आजद देश की राजधानी दिल्ली में यह हुआ। यह उस देश में हुआ जिस देश के लिए सिखों ने बार्डर पर तीन जंगें लड़ीं और हर जंग में अपनी कुर्बानियां दी। सबसे बड़ी कुर्बानी देश में सिखों ने दी। तो वे कुर्बानी वाले, फांसी पर चढ़ने वाले जनेऊ के लिए अपना सीस कटाने वाले, गुरू तेग बहादुर को मानने वाले लोगों का यहां कत्लेआम किया गया और मुझे अफसोस है कि किसी ने उसके दोषियों पर मुकदमा नहीं चलाया, किसी ने उस पर इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठाया, कहीं कोई स्पेशल जज नहीं बैठा और उसके दोषियों में किसी को अभी तक सज़ा नहीं मिली। में इस सरकार की तारीफ करता हूं कि जब इस पार्टी की सरकार दिल्ली में आई तब उन्होंने स्पेशल नए कमीशन बाए, उनसे इस बारे में थोड़े-बहुत कदम आगे बढ़, कुछ मुजरिमों तक पहुंचने के लिए हाथ आगे बढ़े, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी कमी है और आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ फैसले किए हैं कि जिनकी मौतें हुई थीं, जिनका नुकसान किय गया था, उनको कुछ न कुछ मुआवज़ा दियां जाए। जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सारे इंडिया की स्टेट्स में लागू होना चाहिए। मैं तारीफ करता हूं कि बंगाल की सरकार की, वहां ज्योति बसु जी थे, वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई उस समय मैं तारीफ करता हूं डी०एम०के० की सरकार थी

मद्रास में, वहां डी०एम०के० की पार्टी का राज था, वहां कोई ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन मुझे दुख है कि जिस पार्टी का उस समय दिल्ली में राज था, उस पार्टी के राज में, जो अब सैकुलरिज्म का सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीट रही है, इतनी बड़ी ज्यादती हुई और उस ज्यादती के बाद अगर किसी ने बोला तो उसके भी गद्दार कह दिया गया, उसको भी इसके साथ जोड़ा गया कि यह तो देश के हित के अगेंस्ट काम कर रहा है और उसका बोलने का हक भी छीन लिया गया। इसलिए मैं इस हाऊस से कहना चाहता हूं कि अगर हममें जमीर है तो हमें यूनेनिमसली एक रेज़ोल्यूशन लाना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं तो मैं किसी हक के लिए नहीं कह रहा, मैं सारे देश के लिए कह रहा हूं क्योंकि उससे सारे देश की जनता का नुकसान हुआ है। अगर यहां कोई हिन्दू मरता है, मुसलमान मरता है, ईसाई मरता है या कोई वीकर सैक्शन का दलित मरता है तो वह भारत माता का सपूत है न कि किसी एक मां का सपूत है। यदि आप सब भारत माता के सपूत बनना चाहते है तो फिर यूनेनिमसली एक रेज़ोल्यूशन लाया जाना चाहिए। उड़ीसा में दो ननों की मौत हो जाती है तो सारा देश कितना तड़पता है, तड़पना चाहिए भी क्योंकि यह एक सैकुलर कंट्री है, यह इसका विधान कहता है। उस समय दिल्ली में जो आग की लपटें थीं, वे लंदन में दिखाई पड़ीं, अमरीका में दिखाई पड़ीं, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और कोई भी वहां तक पहुंचने को तैयार नहीं कि उन कल्प्रिट्स को सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए अगर ज़मीर है तो हमें मिलकर यह कदम उठाना चाहिए, अगर इस देश को हम आगे ले जाना चाहते है, मजबूत देखना चाहते है तो हमें मिलकर यह कदम उठाना चाहिए।। हमें पोज़िटिव काम करना चाहिए और पोज़िटिव काम के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे बड़े अच्छे-अच्छे आनरेबल मैम्बर इस हाऊस में हैं, वे हमारी जो जतवीज़ है उसको ज़रा-गौर लाएं और मुझे उम्मीद है कि इस हाऊस में यूनेनिमसली यह मता लाया जाएगा। इस देश के सिख के बारे में कभी सोचा जाता था कि अगर वह किसी लड़की के साथ बैठा है तो वह उसकी इज्जत का रखा है, अगर वह किसी कमज़ोर के साथ जाता था तो वह यह समझता था कि यह हमारी मदद करेगा, हमारे साथ एक ताकतवर योद्धा आ गया है, लेकिन अब हमें चोर कहा जाने लगा, डाकू कहा जाने लगा। इसलिए हम इस सरकार को भी कहना चाहते हैं कि जो पिछली कमियां हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, कमियों को घटाने की कोशिश की है, लेकिन पिछली कमियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जाएं और इस बारे में जहां मैं इस सरकार से विनती करता हूं, वहीं सारे हाऊस से भी विनती करता हूं। महोदय, ये 3=4 प्वाइंट मैंने ज्यादा जोर देकर लिए हैं, वहां कुछ और प्वाइंट्स भी है। गरीबोन के लिए 20 लाख मकान बनाने की बात है और टैक्नोलोजी के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां बहुत अच्छी है और खेती में भी लाईफ-इंश्योरेंस स्कीम लागू करने की बात कही गई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, इस थोड़े से समय में इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए है। देश में पिछले 50 सालों की बड़ी-बड़ी बुराइयां फैली हुई है और गरीबी बनी हुई है। मैं बेशक इस धन्यवाद के प्रस्ताव की ताईद करने के लिए बोल रहा हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 11 महीने में सब दुःख दूर नहीं हो सकते। इसलिए जहां मैं अपनी सरकार की तारीफ कर रहा हूं, वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें बजाय लड़ने-झगड़ने के इसे शांति से सुनना चाहिए था और युनैनिमसली धन्यवाद का प्रस्ताव पास करना चाहिए ताकि देश में अच्छी रवायत शुरू हो और सब पार्टियां मिल जुलकर देश की तरक्की के लिए काम करें और हर बच्चे-बच्चे को शांति मिल और देश तरक्की की ओर जाए। इतना कहकर मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): There are 209 amendments to this Address. Amendments Nos. 1 to 26, Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I beg to move:

1. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

   "but regret that the Address does not mention about a targeted time bound plan for eradication of unemployment problem from the country."

2. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

   "but regret that the Address does not mention about implementation of a plan for eradication the rate of production of agriculture produce."

3. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about setting up of an effective system for the benefit of common man by way of transmitting the results of the researches and inventions."

4. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a plan for upgrading agriculture and industry sector of the country above average international level on the basis of new inventions by encouraging research and inventions."

5. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a plan for evolving new technologies keeping in view the indigenous conditions and resources for the sake of development and expansion of agriculture and industry in the country."

6. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a plan for setting up of a system to provide food-stuff of daily use as salt, tea, milk, sugar, rice, pulses, flour to the people of the country living below poverty line at fair price within their purchasing capacity as per their requirements."

7. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a plan for setting up of a system to provide education for each an every child, old and youth of the country by way of including education in the Fundamental rights."

8. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a plan for setting up of a system to make storage of excess rain waters for using it appropriately with a view to make the country flood-free."

9. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of a time-bound scheme to avoid dependency of agriculture on rain waters."

10. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of any time-bound plan to resolve the housing problem in cities, towns and metropolitan cities."

11. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any scheme for bringing transparency in administration, checking the tendency of delaying the work, giving the right of information to common man etc., in order to uproot the corruption from the country."

12. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a time-bound plan to make the expensive and inadquate medical system cheaper and

easily available in the remote areas of the country."

13. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about a time-bound plan to make the prescribed procedure simple and staight forward in order to establish the industries under the self employment schemes of the Government."

14. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of a time-bound plan to make waste-land, available in the country, cultivable."

15. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any scheme to upgrade the education level of the Government Schools and bringing change in existing examination system."

16. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about bringing the prices of products of basic industries like coal, steel, cement, electricity, mining which are being run under the monopoly of public sector or otherwise, and the prices of Petroleum products, Gas, etc. lower than the average prices in the international markets."

17. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation a speical scheme for providing employment to the unemployed youths of the families which are living below the proverty line."

18. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking effective steps for lowering the non-developmental expenditure vis-a-vis developmental expenditure."

19. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any time-bound scheme for providing jobs to every person and making water available for irrigating every field."

20. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any time-bound any target for increasing the purchasing power of Indian currency."

21. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about any resolution for avoiding further delay in completing existing projects which are under construction in a fixed time limit."

22. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the separate industrial policy for the development of tiny ar cottage industries."

23. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of any time-bound plan to encourage the establishment of industries in rural areas of the country by way of providing infrastructural facilities and fixing targets thereof."

24. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking administrative measures to check ever increasing crimes as well as about the scheme for making use of education and broadcasting media for creating clean and ethical environment in the society."

25. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking effective steps for making administration public-welfare oriented."

26. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about taking effective steps for checking unbridled price rise of commodities in the daily use of common consumers in the country,"

श्री रमा शंकर कौशिश: मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

30. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

31. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती मंहगाई पर रोक लगाये जाने के उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

32. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवाद को समाप्त करने के उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

33. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अराजकता को समाप्त करने और कानून का शासन स्थापित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया"

34. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

35. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी उपक्रमों को बेचकर निजीकरण पर रोक लगाने के उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

36. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक क्षेत्र में बहुराष्ट्रिक कंपनियों के प्रवेश पर रोक लगाने के उपायों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

37. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (संघ परिवार) से संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

38. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समान प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"

SHRI C.P. THIRUNVUKKARASU (Pondicherry): Sir, I beg to move:

71. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the implementation of any long term or short term policy for the improvem entof Textiles, specifically spinning mills."

72. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention any time bound plan to improve tourism in the country."

73. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention any time bound plan to include all the Indian languages in the VII-Ith schedule of the Constitution of India."

74. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the reservation of 33% seats for women in the Parliament and Assemblies."

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I beg to move:

75. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the statutory dues to Central public sector units workers."

76. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention any specific steps to involve the labour as equal partner in national reconstruction."

77. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention how the resources will be mobilised to step up investment substantially in the infrastructure sector."

78. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention what specific measures will be taken to reach out the underprivileged and unemployed."

79. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the measures to recover the excessive subsidy to the tune of Rs. 1000 crores drawn by some private urea manufacturing companies through 'gold-plating'."

80. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steps to curb the activities of the organisations directly or indirectly involved in inciting and organising attacks on minorities."

81. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the socio-economic impact of the Government's decision to privatize or corporatize core sector industries like power, coal, oil, airports, ports, etc."

82. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the severe impact on Eastern zone States because of the recent hike of power tariff by more than 40% by NTPC in its Eastern zone power stations in Farakka, Kahalgaon and Talcher."

83. That at the *end* of the Motion, the following be *added,* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the hardships caused to the common man due to lowering of interest rates for small saving schemes."

84. That the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about hike in the prices of essential commodities sold through Public Distribution System."

85. That at the *end* of the motion, the folowing be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about hike in the administered price of urea and cooking gas."

86. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about sickness of inudstries and steps to arrest the industrial sickness."

87. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about revival of sick public sector units like IISCO, Jessop, Burn Standard, National Instrument, MAMC, BOGL, Tyre Corporation of India, Hindustan Cables, Durgapur and Haldia units of Hindustan Fertilizer Corporation, NTC, NJMC, Jute Corporation of India, Bengal Immunity, Smith Stanistreet, Cycle Corporation of India etc."

88. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about granteeing minimum wages to agricultural labours."

89. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about recognition of single trade union through secret ballot."

SHRI SANATAN BISI: Sir, I beg to move:

90. That at the *end* of the motion, the following be *addes* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the causes of the activities and performance of the Government in the last one year."

91. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention regarding effect of letter sent to the U.S. President by our Prime Minister after nuclear tests at Pokhran."

92. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention regarding the various activities of various Task Force."

93. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention any measures of safeguard the secularism."

94. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that that Address does not mention about the assurance of the Government that it will not in any manner directly and indirectly attempt to subvert the Constitution and float Democratic norms and standard."

95. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the assurance of the Government that it will not alter the basic structure of the Constitution which guaranteed independence of the judiciary."

96. That at the *end* of the motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not specify/qualify the concept of the worlds "National Agenda for Governance."

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir I beg to move:

124. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the address does not mention about the failure of the Government to check the atrocities against the minorities in certain States."

125. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address failis to mention as to why article 356 of the Constitution was invoked only in Bihar while the same situation of law and order is existing in Gujarat and Maharashtra which is further deteriorating every day."

SHRI SURESH PACHOURI Sir, I beg to move:

183. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not reflect Governments firm determination to protect the minorities from the onslaght of the fundamentalist organisations like Bajrang Dal Vishwa Hindu Parishad and Rashtriya Swayamsewak Sangh who have unleashed a volley of terror amongst the minorities by burning them alive and their properties and religious places, raping the nuns and violently attacking their families in various parts of the country particularly in Gujarat."

184. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not relfect Governments firm determination to direct the State Government to direct the State Government of Gujarate to stop forthwith the Census of Christians and Muslims through State Police which has sent shockwaves amongst these minority communities in that state and other parts of the Country.

185. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the steep hike in prices of essential commodities particularly after the hike in prices of PDS ration items, LPG, urea which has caused immense hardships to the poor and the farmers throughout the country."

186. That at the *end* of Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about the package for the overall development of Madhya Pradesh."

187. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing resentment amongst the youth of the Country resentment amongst the youth of the Country due to lack of employment opportunities for them resulting in their joining hands with the anti social and anti national elements thereby becoming a threat to the national security."

188. That at the *end* of the Motion, the follwoing be *added* namely:—

"but regret that the Address does not mention about the growing Comunalism and fundamentalism in the country."

189. That at the *end* of the Motion, the following be *added* namely:—

"but regret that the address does not mention about the problems of Bhopal Gas victims of 1984 and timely solution of their problems."

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I beg to move:

190. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address does not mention about harnessing underground water for providing irrigation facilities to rainfed areas."

191. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address dfails to mention that all the benefits of reserach and subsidies for famrers are enjoyed by only 30" of farmers of country and no proper plan of assistance is contemplated far 70% of the Small and marginal farmers."

192. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the implementation of land reforms in order to implement the scheme of 'Land t the Tiller'."

193. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the problem of unemployment in rural areas and plan to provide gainful employment to the rural unemployed people."

194. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the indiscriminate urbanisation thereby creating increased social problems and the necessary remedy to stop the same."

195. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mentionabout the increased unemployment of enducated youth and their frustration and to take remedial measures."

196. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the required changes in the education system in order to make the individual a selfmade man to earn his livelihood after education."

197. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about creating vocational training centres in large scale to absorb educated unemployed youths."

198. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the growing frustration among the youths who are becoming antisocials and militants

and to take remdial measures for solving their problems."

199. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the shortage of Power in various states and steps to augment the same."

200. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the proper distribution of infrastructural facilities to all parts of the country in order to have a balanced development."

201. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the anomalies that have crept in the implementation of Reservation and suggest proper remedies."

202. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about providing equal opportunities to SC/ST and weaker sections at the higher hierarchy of the administration i.e., at the desision making level."

203. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about frustration among the SC/ST lpeople because of the anti-reservation action taken by the Government by curtailing certain facilities enjoyed by them all these years."

204. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the non-following of the Planning Commission's guidelines in allocation of funds to S.C.P. and T.S.P.

205. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention the remedial measures to plug the misuse or diversion of S.C.P. and T.S.P. funds allotted for the amelioration of SC/ST people."

206. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about bringing a law to provide reservation and make it justificable."

207. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about increasing residential schols for S.C. and S.T. children so as to improve the literacy in order to bring them to the mainstream."

208. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about the discrimination and humiliation suffered by certain class of people on caste basis and take proper action."

209. That at the *end* of the Motion, the following be *added*, namely:—

"but regret that the Address fails to mention about providing proper opportunities to S.C. and S.T. people in Trade, Commerce, Industry, Foreign trade ad High Technology opportunities."

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI Md. SALIM): The motion and the amendements were moved. They are now open for discussion. Shri Manmohan Singh.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir we are very grateful to the Hon'ble President for his Address, but I must note with deep regret that the Address does not project any clear vision,

a well-thought strategy or an action programme to deal with the formidable challenges that our country's economy, polity and society face as we enter the 21st century.

In paragraph 2 of the President's Address, it is stated, and I quote "As we approach a new century and a new millennium, our hopes, aspirations and expectations for the coming era should be matched by sound and determined efforts now." Sir, in vain, do I look for that lofty ground in this Address. This is an Address prepared by a Government which has lost any sense of purpose. It is a non-performing Government. It is a squabbling Government and I say so in deep sorrow, not with any sense of anger.

When this Government came into power it was advertised as a Government having an able leader seeking to provide a stable Government. Today, it is a disabled Government for more than one reason. Eleven months have passed and the Prime Minister is unable even today to complete his Cabinet . He had announced a date, I remember, on 15th of December, but for reasons best known to him and his colleague in the Home Ministry probably, he could not fulfil that expectation. Two or three Ministers of this Government left under a cloud soon after this Government came into existence. Another senior Minister of this Government left because he could not bear the high-handedness of some of the entities which are close to the ruling establishment. And today, we have three important Ministers of this Government becoming a subject matter of serious controversy. We have heard about the handling of the Bihar case by the Hon'ble Home Minister. His statement about an apolitical Governor and apolitical administration is now seen; for what it was, i.e. an attempt to create a set up whose objectives are suspect. Also, the Home Minister has appointed a Commission of Inquiry to look into the tragic incidents that took place in Orissa where three innocent persons were burnt alive. This incident was great national shame, a matter which the Hon'ble President of our country himself described as a monumental aberration. And yet, when allegations are made about certain entities like the Bajrang Dal or the Vishva Hindu Parishad, the hon'ble Home Minister had the temerity or the audacity to say in a public statement that he knows these organisations, there are no criminal elements in them. If the Home Minister of this country stoops to this level, how are the constitutional liberties of our people going to be protected?

3.00 p.m.

Then we have seen the sad Bhagwat affair. Since 30th of December, newspapers have been writing about it. The Government has been putting out handouts through selected privileged people. We have also heard the former Naval Chief coming out with a statement. I don't want to assess or apportion the blame. But it is for the first time in the hisotry of independent India that as high an official as a former Naval Chief has levelled serious charges against the functioning of the defence establishment.....

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Under which rule?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, this matter is *sub judice. (Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I am not allowing you. Please sit down.

आपको मालूम है कि प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का कोई तरीका होता है?

DR. MANMOHAN SINGH: I am not apportioning the blame. I am merely stating the facts which are known to all the people in the country. It is the solemn obligation of Parliament to investigate, to satisfy itself whether these charges are right or wrong. It is in that spirit of sorrow that I am highlighting these things. It is for the first time in the

history of independent India that a Naval Chief was dismissed in such a manner. It is for the first time in the history of independent India that a former Naval Chief has accused the Defence Minister of several illegal acts. He has charged him with subverting the chain of military command, destroying the civil—military relationship and undermining the disciplinary framework of the armed forces. He has of alleged that armed peddlers are subverting the Navy. A far more serious charge which he has levelled is that the Defence Ministry ordered non-interception of some illegal armed shipments in the Andaman seas. I am not naming 'to whom'. But these are very serious charges. It is absolutely imperative that...

SHRI SANGH PARIYA GAUTAM: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Under which rule?

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: My point of order is this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): You start with quoting the rule.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I will quote the rule.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please sit down. I am not allowing you. (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Sir, listen to his point of order. यह पवाइंट ऑफ आर्डर तो आपको सुनना ही पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): मल्होत्रा जी, आप तो पुराने सदस्य हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि प्वाइंट ऑफ ऑर्डर कैसा होता है? He is not quoting any rule. (*Interruption*). Except what Dr. Manmohan singh says, nothing will go on record.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Mr. Malhotra, I will name you. I have given him a chance. He is not quoting any rule. He should know how to raise a point of order.

प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा: किसी मिनिस्टर के खिलाफ.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please sit down. I am going to name you.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Sir, I want to raise a point of order. किसी मिनिस्टर के खिलाफ.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I am not allowing you. आप सभी खुद ही बोल रहे थे। आप अपनी बात के ऊपर खुद प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं कर सकते। उनको बोलने दीजिए, उसके ऊपर कोई प्वाइंट ऑफ आर्डर हो सकता है। You cannnot raise a point of order like this. आपके इमीडिएट पहले तो आप ही बोल रहे थे। आप उसके ऊपर कैसे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं! ....(**व्यवधान**)...बैठ जाइए, ...बैठ जाइए...(*Interruptions*). He is not levelling any Charges. सुनिए उनको

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: These are charges against the Minister.

DR. MANMOHAN SINGH: I am not levelling these charges. These charges have been levelled by the former Naval Chief. We would like these charges to be investigated in a thoroughly objective manner. What does all this show? These things show that all is not well with the management of the country's defence affairs. And that should be a matter of serious concern to the Members of this House.

Sir, in the last few days, we have received information in the form of an article, signed by a former adviser to the Finance Minister, which raises serious issues concerning the management of our economy. In this article, Mohan Guruswamy has levelled serious accusations against important Ministers of the Government and the PMO. And what he has said is quite contrary to what Mr. Malhotra has said that there is no corruption in this set-up. Mr. Guruswamy has given several instances of the worst cases of chronic capitalism prevailing in the last 11 months. I am again not here to tell you whether these things are right or wrong. But these House has a right to

know what the truth is. In this article of Mr. Guruswamy, it is mentioned that the Finance Minister intervened to determine a share price, the price which a particular company's share should fetch, when that share was to be sold by the Unit Trust of India. I have never heard Finance Ministers settling individiual share prices. It would be a sad day for our country where the Finance Minister, sitting in his office, would decide what should be the price of a share or who should but it or who should sell it. I have often said that our financial system gives the Finance Minister of the country trememdous power, and a scrupulous Finance Minister can overnight transform this economy into a collectivist economy without the passage of any Bill in Parliament. Therefore, when we read that the Finance Minister of this Government has been a party to these things, it disturbs me. I hope that the Government, when they reply, would clarify what the position is. Then, there are certain bail-out operations worked out for individual steel companies. And, in this article, it has been stated that for a particular enterprise, a bail-out package was worked out in the presence of the Finance Minister, in the presence of the concerned industrialist. I submit that this is a strange way of taking decision. Finance Minister can lay down policies. He can give directions on policies. But for him to determine what particular loan will be given to a particular individual company is something which is not consistent with the canon of good governance. We would like to know from the Finane Minister what his role was is negotiating the deals for one of the steel companies. And, more shocking — if this is true, it involves not one Minister, but three Ministers — is that recently there have been complaints about the dumping of some types of steel into our country. Perhaps, rightly the Government decided that they should fix the referral price, below which we would not like to allow imports, so as to protect our industry. I do not grudge that decision. But it is alleged in this article that an inter-Ministerial team had fixed that referral price at 247 dollars a tonne. But, finally, the price that was announced was 302 dollars a tonne, and thereby according to Guruswamy's calculation, on certain people a benefit close to Rs. 5,000 crores. He also says in this article that as to how and why the referal price was fixed at a much higher level is not known to the officials, and the people who know how this happened are the three Ministers of this Government, namely, the Finance Minister, the Minister of Commerce, Shri Hewgde, and the Minister of Steel, Shri Naveen Patnaik. It is their responsibility to come clean to enlighten the House whether what is stated in the article of Mohan Guruswamy, who was, until two or three weeks ago a senior officials of the Finance Ministry, is true. These things need to be clarified. But whether you like it or not, this does not give us an idea that this is a functioning government. This very article of Mr. Guruswamy brings out a Prime Minister at war with his Home Minister, a Prime Minister not trusting his Finance Minister, a Communications Minister differing with the Prime Minister. When important decisions are taken, individual Ministers do not feel responsible because they have had no hand in taking those decisions.

In the morning, Mr. Malhotra referred to this big plan of building roads. Let me read out what Mr. Guruswamy has written about that road plan, and I crave your indulgence.

> "Compounding his well known lack of attention to detail was not his very known attention to problem of deficits. One fine morning, the Prime Minister announced a grand plan for a 7000 Km. long *de novo* six-lane highway system from Jammu in the North to Silcher in the East. He estimated this NSED highway project to cost Rs. 28,000 crores at four crores of rupees a kilometre when it should be about Rs. 12 crores a kilometre. Highways

are supposed to carry goods and people which means they join markets and population centres. Here, they Prime Minister was proposing highways from nowhere to nowhere and at a cost that was understated by at least a factor of three, that is, he was stating that he would be building for Rs. 28,000 crores what should be costing Rs. 84,000 crores. Neither the asministrative Ministry nor the Finance Ministry were consulted and after the announcement was made, few had the courage to tell the emperor that he was not wearing any clothes."

And this is the quality of administration. All Ministers make statements, grand statements, policy statements unbacked by any study, any project detail or financial resources. Even to this day, we do not know how this ambitious road plan is going to be financed. Such is the level of competence that this Government has.

As I said, I say so in great sorrow because India is a country of tremendous potentiality. At a time when the rest of Asia was downcast, we could have been a shining star. If we had conducted our economy well, we could have been the beneficiary of a lot more inflow of capital for infrastructure and other purposes. But what has happened? Since this Government came into office, because of its obscurantist policies, the flow of investment has declined month after month. If and the result is, an atmoshphere of drift prevails, and this drift is hurting this country very dearly. That is why confidence among the investors is an all time-low, confidence among the consumers is an all-time low. The fact that Indian industry is growing at not more than 3.5 per cent is an indication of that. The President's Address mentions the Ninth Plan. I have read this document. I don't think there has been a studied application of mind in preparing this document. This document is so badly written that evey I had a great difficulty in understanding what are the assumptions on which its resource calculations have been made. The Plan projects an average growth rate of 6.5 per cent. Two years of the Plan are already over. Now, if we are going to get a 6.5 per cent growth for the Plan, the economy must grow at the rate of 7 per cent in the next two years. Neither in the President's Address nor anywhere else we are told how we are going to get a 7 per cent growth, with the current industrial growth being 3.5 per cent and with the current export growth being negative. These are the issues which are totally glossed over in the President's Address, and, at the end, we are left wondering where this Government is leading our country to, standing as we are, on the threshold of the 21st century, and a new millennium.

Sir, I was saying that we need a new beginning; we need a new type of politics, a politics of morality and creativity; where politics would be seen as an instrument of purposeful social change, and that requires a rethinking about many things which all the political parties have been doing. But the first and the foremost task before our country is to preserve the unity and integrity of India by remaining firm and steadfast in our commitment to secularism as enshrined in our Constitution. Ours is a multi-ethnic, multi-religious and multi-linrquistic country and this diversity is a product of our eternal search for truth. We are richer for it. India is the greatest storehouse of religious and philosophical thought that you find anywhere else in the world. We have to preserve this precious heritage. It is only by respecting our diversity that we can strengthen our unity. Yet, in the last eleven months that this Government has been in office, sustained efforts have been made by parties and elements close to the ruling group to fan and foment vicious communal discord and strife. Deliberate efforts have been made by the Bajrang Dal and the VHP to promote a culture of hatred and violence targeted at religious

our Balance of Payments and reserves look comfortable, as Mr. Malhotra tells us, it is because of the four billion dollar bonds that we raised—very high cost bonds. I do not disapprove of those bonds. But what will we do the next year? We have today an extraordinary situation in the country. The oil prices have declined by nearly fifty per cent in the last one year. That should have been a big benefit to India's Balance of Payments. But in spite of these soft oil-prices, India's trade deficit has more than doubled. India's Balance of Payments deficit has increased greatly. If we go on this same path next year India will be in the midst of a severe Balance of Payments crisis. This is not a record of achievement. It is a record of non-performance. For the first time in the last seven or eight years, exports have declined in absolute terms. Industrial growth rate this year has reached the lowest level in the last seven years. The growth rate in April-December was not more than 3.5% per annum. This is a year in which despite the good crops which have saved us—and therefore, the Government can say that the economy is growing at the rate of 5.8 per cent—despite a five per cent increase in agricultural production, the food prices this year have risen by an all time high of 18 per cent. So, the poor are the sufferers. Now, you are going to superimpose upon them additional sufferance by this hefty increase in the prices of items supplied through the public distribution system.

When I look at the problems of infrastructure, I find a large number of committees, a large number of groups, but they all add up to nothing because this is a Government where nobody is really accountable. Everybody is making policy for everybody else. The Prime Minister is making policy for everybody else. His Ministers don't feel happy. They don't implement it. One does not know, for example, what the end result is. The Prime Minister in a Conference of FICCI made a statement that within 15 days, he would resolve the dispute about telecom licences and the difficulties that had arisen between TRAI and the Department of Telecommunications. Four months have passed. Nothing has happened. The dispute remains unsettled; this is one case where, if this Government had shown any ingenuity, large flows of foreign investment and domestic private investment would have immediately come into this sector because they are all waiting for a fair solution of the disputes that have arisen. I am not arguing about how these disputes should be settled. But it is the responsibility of the Government to settle these matters. They are not being settled, minorities, vicious propaganda machinery is now actively at work to tarnish the fair image of the tiny Christian community. It is a small community, Sir, of less than 20 million people and the members of this community have been very active in public service, particularly in the field of health and education.

As has been pointed out by the Chairman of the National Commission for Minorities, Dr. Tahir Mohammed, the common man belonging to the majority community is given to believe, as Mr. Malhotra today tried to do, that every single Christian in India is out to convert Hindus to Cristianity, which is, of course a totally false proposition. I was saddened to know that at the recent Dharma Sansad, convened by the VHP at Ahmedabad, a resolution was allowed to be adopted calling for action to save the nation, culture and religion from the international consipracy of converting India into a Christian nation. It is this sort of vicious propaganda, vicious resolve which is going to destroy the unity that we all seek. The power of propaganda is unfortunately so strong that when I travelled in various parts of India, I saw a vicious compaign going on today, all over India, on these lines and the common man is being misled to believe in these things; and there lies a great danger to the Republic that we cherish.

The tragic incidents in Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa are a direct outcome of this vicious propaganda and it is indeed most regrettable that even the Prime Minister has chosen to say that conversion is a problem and that there should be a national debate on it. The advocates of such a debate forget—perhaps, they know and deliberately forget-that the right to profess and propagate the religion of one's choice, subject to public order and morality, is a Constitutional right and that there are enough legal safeguards against forced conversions which rought to be condemned in any way. They are vociferous in their allegations about forced conversions but when the National Commission for Minorities asked the Gujarat Government, they were not able to produce any statistics to prove the cases of these conversions. Indeed, today, we have a situation where the Bajrang Dal and the VHP have drawn up a massive programme of what they describe as 're-conversion', which, we must recognise, has given rise to a grave sense of insecurity and fear among the members of the small Christian community in many parts of our country.

We are grateful to the President that in paragraph 8 he has said that the Government is firmly committed uphold secularism which has deep roots in our society and polity and that the recent incidents in Gujarat, Madhya Pradesh and Orissa have caused us anguish. The Address goes on to say that these have to be seen as aberrations which do not reflect the national ethos. The Address also states that the Government is fully committed to the protection of minorities. I welcome these sentiments. Yet, Mr. Vice-Chairman, Sir, the proof of the pudding is in the eating. We have authoritative statement from the Chairman of the National Commission for Minorities, published in **The Economic times** of 31st January, 1999 that this Commission has positive evidences of involvement of the Bajrang Dal and the VHP in attacks on minorities. When I put a question to the Home Minister this morning on this very issue, a wholly evasive reply was given. Also how we can forget that in spite of evidence provided by the National Commission for Minorities to the Home Ministry, the Home Minister has the audacity to give a clean cit to both these organisations saying on 1st February, 1999, "I know these organisations. They do not have any criminal element." We have the BJP Government in Gujarat, for reasons which can be guessed which has ordered a so-called census of Muslims and christians in Gujarat through its police force. If this Govenment's profession, its commitment to secularism and protection of minorities are to be taken seriously, then it must take strong and effective action to stop the hate campaign so aggressivcly being launced by the VHP, the Bajrang Dal and their associates. Yet we all know that the Government has done precious little in this regard. The BJP leadership's pledge to rein in the Sangh hawks has all been an eye-wash. Its own allies such as Lok Shakti Trinamul Congress and the AIADMK, have testified to this effect clearly. It is, therefore, not surprising that there is a complete erosion of our people's confidence in the credibility of this Government. This thing cannot be kept hidden from the rest of the world. And the fact that India gets such a bad international Press is not merely because of these incidents, but the hate campaign that lies behind the mand the viciousness with which that hate campaign is being promoted and encouraged in large parts of India. In recent months, the newspapers have been agog with publications that the frontal organistions have zeroed in on 67,000 villages in our country where these so-called re-conversion drives will be launched. Now, this sort of a thing can be an instrument of only further dividing our people, sowing seeds of hatred and discord. If this Government does nothing to prevent this sort of a thing, its credentials, its

profession about protecting the minorities, about protecting the secularism cannot be taken at their face value.

Sir I shall now say a few words about the subject matter of defence. In para 6 of the President's Address, it is stated, "The nation expresses its gratitude to the brave jawans and officers of the Armed Forces and other paramilitary forces who have laid down their lives in fighting the proxy war unleashed by terrorists. The country recognises the sacrifices of those posted in places like Siachen and other remote border areas in the service of the nation."

We whole-heatedly agree with the praise of our brave jawans and members of our armed forces. But, I must also point out to the Government that the manner in which the Naval Chief had to be removed some months ago, has given rise to a good deal of bitterness, dismay and unrest in our armed forces. Admiral Bhagwat's statement, a few days ago, has raised serious doubts about the proper functioning of our defence establishment under the present Government. The least that this Government can do is to order a high-powered independent enquiry, if necessary, in-camera, to look into the affairs of Bhagwat and the issues that have been raised by it. Mr. Vice-Chairman, Sir, our goal should be to maintain the a political character of our armed forces. Also, the vivilian control of the armed forces is a matter not for dispute. At the same time, we have also to ensure that the morale of our armed forces is as high as is humanly possible.

The hon. Defence Minister has been talking about restructuring the defence set-up. We are not against restructuring. But, a structure which has been created over fifty years cannot be restructured in a month or two or three months. If he has any ideas of restructuring, we would urge the Government that those ideas should first be discussed with the Members of Parliament and other interested expert bodies. We should not be present with a *fait accompli*. Any decision in haste, I think, would be a very unwise act. I read that he has planned of restructuring the defence system in one month. That clearly is impractical and no hasty decision should be taken without effective consultations with all knowledgeable persons, including the major political parties. A party like ours which has served as a ruling party for fortyfive years cannot accept a proposition that this present old system can simply be dismantled by a new system without any careful thinking. One request I would like to make to the Government is that they should not go after restructuring in a light-hearted manner which has been the charcteristic of this Government, the way it has been doing many things for the last one year. The second thing I wish to say is that the Government indeed has set up the National Security Council. But, whosoever has commented on the set-up of its advisory bodies and all the paraphernalia, says that it is an unworkable and un unwieldy body. I urge the Government to have a look at the monstrous structure that they have created. I also recall Mr. Malhotra saying today in this house that they remain faithful to the National Agenda. The National Agenda had promised that the Government would come out with a National defence Review. We are still waiting for the National Defence Review. Sir, Pokhran Tests have come and gone. We had hoped that the National Defence Review would have preceded the Pokhran Tests. But that expectation was belied. But, even today it is not too late to come out with the National Defence Review that was listed in the National Agenda.

Mr. Vice-Chairman, Sir, we recognise that after the Pokhran Tests, a new situation has arisen with regard to the security environment in the South-Asian Region. India and our neighbours need to negotiate the norms to stabilise the South-Asian nuclear environment and to

set a new course for regional nuclear safety and co-operation. Therefore, we welcome any steps taken in that direction. We also welcome the initiative that was taken at Lahore. We endorse the statement made in the Lahore Declaration that India and Pakistan should take immediate steps for reducing the risk of accidental or unauthorised use of nuclear weapons and discuss concepts and doctrines with a view to elaborating measures for confidence-building in the nuclear and conventional fields, aimed at prevention of conflict. However, I would urge that these confidence-building measures should not be left merely to negotiations between India and Pakistan. We must resume the dialogue with our big neighbour in the North, that is, China. We cannot have a situation where India's relations with China remain frozen at the present level. The last one year has been an year of retrogression in these relations. I think, this Government must act speedily to make up for the lost time. I know, the Government, at high levels, have held discussions with all the major nuclear powers, but not with China. We would like to know as to what are their plans with regard to resumption of a similar dialogue with China, which, I believe, is essential for a lasting era of peace, security and prosperity in this region that we live in.

Sir, now I come to the Foreign Policy of India. In the field fo Foreign Policy, until the Pokhran tests, there was a remarkable unanimity in the country, and that is as it should be. We can differ on domestic policy. But when we face the rest of the world, we must face them as one nation, united, knowing what is in our national interest. It is a sad reality that the Pokhran tests disrupted that sense of cohesion and common purpose, which guided India's Foreign Policy till then. It is the responsibility of the Government to act and act decisively to restore once again that common sense of purpose and bring about once again a national consensus about the conduct of our Foreign Policy. In this context, I must confess that we face today an odd situation. Negotiations have been going on between Mr. Jaswant Singh and Mr. Strobe Talbott. But, what has been happening in these negotiations? We have had a general statement made by the Prime Minister. It is really unfortunate that we have to go to Mr. Talbott or to the American Spokesmen to really know what has been happening in these negotiations. We know from Mr. Talbott more than we know from our own official spokesmen. I suggest this Government that this is not a healthy state of affairs. They should come out clearly as to what is the current state of the play. The American news media has widely reported that this Government is going to sign the CTBT in May, 1999. This Government should tell this House whether any such assurance has been given to the Government of United States. If this assurance has been given, what has been the *quid pro quo*. What has happened to the conditions mentioned by the Government spokesmen soon after the Pokhran tests? Have the American and their other partners agreed to abide by those conditions? This Parliament is entitled to know the state of the play of these negotiations, as well as the state of the play of the negotiations that this country has held on nuclear issues with France, United Kingdom, Russia and also with Japan, though it does not happen to be a nuclear power. We would like to know the consequences of signing the CTBT because even today I read an American spokesman saying that even after India signs the CTBT, there will be no automatic removal of the economic sanctions that have been imposed on India.

Now on all these things, if we have to have an informed debate in our country, in the expectations, that ultimatley there must be a broad national consensus, please give us information, please give us reliable data on the basis of which we can

make up our mind. Don't treat Parliament with such scant respect as has been the case thus far.

Mr. Chairman, Sir, as regards our relations with neighbours—and Mr. Malhotra brought up this subject very early—we have no reason to grudge or grudge giving praise where it is due. If anything that can be done or is done to normalise the relations between India and Pakistan, to ensure that problems which have persisted are resolved, if honest efforts are made to resolve them step by step, our party will be fully in support of all such efforts. We do recognize that Mr. Vajpayee's initiative, even though nothing concrete has emerged except updating in one form or the other the language of the Shimla Agreement. But even then, it is an achievement. Therefore, we as a Party, we as Indians have a vested interest in the success of meaningful negotiations between India and Pakistan and I fully endorse the Prime Minister's statement that a strong, secure, stable and prosperious Pakistan is in India's interest just as a strong, stable, secure Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, Sri Lanka are equally in India's interest. On this point there is no difference among the political parties in our country. Therefore, on this point it should not be said that we have taken a decision on Bihar because we do not like Mr. Vajpayee's stealing the shine with regard to what happened in Lahore. That was far from our thought and I will explain in a moment why we did in Bihar what we actually did. But I would like to cuation the Government. On the very day when the two Prime Ministers were winning and dining, 27 innocent lives were lost to terrorist acts in Jammu and Kashmir. And I agree that words have meanings, but deals sometimes speak a lot more and it will be very difficult for any Government to sell this *Bhai-Bhai* approach if, on ground, innocent people are being butchered day by day. Therefore, it is incumbent on the Government to make it quite clear to the Government of Pakistan that if these negotiations have to more forward, then these dastardly terrorist acts, aided and abetted by the ISI, must come to an end. Otherwise, as has very often happened in the past, good intentions may not fructify into solid acts of achievement. History is replete with such instances and I hope that the Lahore conclave does not end up with a similar fate. We have a vested interest in the success of these negotiations, but we must not be romantic. We must keep our feet on the ground.

Sir, now I wish to say a few words about the internal security. In paragraph 9 of the Address, the President has noted "with considerable satisfaction that terrorism and subversive activities in various parts of the country are being effectively contained." But we all know what is happening in Jammu and Kashmir. I must confess that what is happening in the North-Eastern States is perhaps not being projected to the consciousness of the nation. The insurgency in most of the North-Eastern States has become the norm. The sad reality is that there is the Government's rule during the day, but insurgents' rule at night. The life for the ordinary people in many States of the North-East has become, what Hobbes once described, nasty, brutish and short. Therefore, this statement is too much simplistic and complacent particularly when it talks about the insurgency situation in the North-East.

I am particularly disturbed about what has been stated in paragraph 10. It has been stated:

> "The Government of India is considering repeal of the Illegal Migrant (Determination by Tribunals) Act, 1983."

This statement is likely to give rise to a serious anxiety and a sense of fear among the minority community in Assam. This matter was settled long ago through Rajiv Gandhi's Assam Accord. Opening it once

again will create grave dissatisfaction among the Muslim community which is 30 per cent of the population of Assam. Past experience shows that any reversal will be an act which will be looked upon as a positive discrimination against the minority community.

Therefore, I would urge upon the Government not to take this hasty action. If it ever brings such a Bill to Parliament, as a party we will not support it.

Sir, about the economy, I have already siad-enough, and I do not wish to say more. The Address talks about the Government's commitment to the social sector. We all know the critical role of universalisation of the elementary education. Yet, very little has been said about this important area in this Address. Our Government in 1995-96 started a nation-wide Mid-Day Meal Programme because judging from the situation in Tamil Nadu, we found that one of the best ways to get children to school is to provide them with the mid-day meal. This is a wholly Centrally supported Scheme. My information is that this Programme is languishing. There is no word about the progress of this important Programme which can have a massive impact on getting our children into school. In the year 1995-96, we started a nation-wide programme of antional social assistance, providing Rs. 300/- to every pregnant woman so that at the time of confinement or during pregnancy she can buy essential medicines. We also started a nation-wide programme of old-age pension, financed by the Central Government. All these programmes are languishing for the last three years. No word has been mentioned about the progress of these schemes in the President's Address. I want the hon. Prime Minister at least to make a mention about the Government's commitment to these programmes when he replies to the debate.

In the same way, there is not a word in this Address about the vital Family Welfare Programme. We all know about the degradation of India's land, water, air and environment, and this has received scant attention in this Address.

So, I could go on, Mr. Vice-Chairman. But, as I said, the Government is probably too preoccupied in resolving conflicts either among its allies or among the various members of the Parivar themselves so that a sensitive, sensible and pragmatic policy-making has taken a back seat.

We have now an admission by no less a person than the hon. Home Minister that the Government faces a situation where even parties with two or three Members can dictate terms and blackmail the Government. This is not an atmosphere in which a purposeful, meaningful, thought-provoking action can be taken.

Now, I come to the last area—the State of Bihar. Mr. Malhotra referred to this case. I will be very brief on this. Sir, we are an Opposition Party. We are the largest Opposition party in the Rajya Sabha. The BJP knows very well that no legislation of this sort can be passed in this House if it does not enjoy our support. And yet, I am honestly saying, at no time the BJP made any effort to talk to us on this subject to say that a situation existed in Bihar, where, in the national interest something like this needed to be done. They knew our view previously when they brought the first proposal. We publicly opposed them. In the light of that, as a responsible and a responsive Government, it was their obligation to consult us, we being the largest Opposition party here. They should have told us that this was the problem and we should jointly apply our mind. Nothing of that sort was done. To assume that the proud Congress Party will do the BJP bidding under all circumstances, is something which they should never expect. Let me be quite clear. . .

श्री संघ प्रिय गौतम: देर आयद दुरूसत आयद।

DR MANMOHAN SINGH: We cannot endorse the Government's action in invoking Article 356 in Bihar. It is not because we are not worried about the state of affairs in Bihar. We are worried about the state of law and order there. We are worried about the deteriorating economy; we are worried about the atrocities on Dalits, but we are still not in favour of Article 356 being invoked, because we have no confidence that an administration controlled by a confirmed Member of the RSS will provide any assurance that this Government will have the will and power to deal effectively with entities like the Ranbir Sena. The class composition which the BJP and the Samta party combine represents does not provide us any assurance that a Government dominated by this class will take any effective action against the sordid activities of the Ranbir Sena. The imposition of the President's Rule under Article 356 is, in our view, not based on concern for law and order or concern for atrocities on Dalits as Mr. Malhotra projected, but it is designed to push the parochial political agenda of the BJP-Samta party combine. We shall never be a party to this. That is our position. With this I conclude.

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, I thank the Prsident for the address, but I regret to say that this address does not present the grave realities, which are being faced by the nation. It lacks clear direction for a way out from the nightmarish situation we are facing today.

[Vice-Chairman (Shri Sanatan Bisi) in the Chair]

Before I came to the Presdient's Address, I wish to make a point about the statement of Admiral Bhagwat, former chief of Naval Staff. He had made a very serious statement that "the Defence Minister had gone beyond his legal status. He had done a big damage by disrupting the equation between the Army and the Civil officials." This is the first point. The second point he had made was, "He had done so many other things." I do not want to go into those details. But the point is any Government which has some sense of shame ought to have come out with the facts. Mr. Fernandes ought to have resigned from his post. That is the minimum candition any Indian can expect because the Armed Forces are not sector wherein a Government comes for some period and meddles with their affairs. This Government may go tomorrow. The equation and the balance has been kept in India for a long time. Our Armed Forces are unique. Hitherto, for the last 50 years, there was no such complaint or difference from the Government on this question. Everything has been done on the set pattern, keeping equanimity between different sections of the personnel. Now it has been disturbed. it has also been stated that he has some connections with the LTTE, etc. I do not want to explain it. But I demand that Mr. Fernandes should step down. The other question can be discussed later. This is the first point I wanted to make.

Now I will come to the President's Address. The President in para 3 has stated that implementation of the "so-called" National Agenda in the past eleven months has instilled a new sense of self-called" national Agenda in the past eleven months has instilled a new sense of self-confidence among Indians. We know about the situation prveailing in the country India is not a small island. India is a big country having nearly 100 crores of people. We have evolved a Constitution in which ours country can be a united nation with different cultures, with different religious groups—christians, Muslims, Buddhists, etc. who are all Indians. Secularism is the basic foundation of our Constitution. We have seen the experience of pakistan having a Government based on their religion. But it was broken into two countries within a short span of time. But India stood the test of time because our Constitution is such that it has a basic foundation in

which every section of the society has been quaranteed a right, without anybody's interference. They claim that the "so-called" National Agenda which is being put into practice is good. What the real agenda is not told to us. But we know what the real agenda of the parties which are supporting this Government. We know that the Sangh Parivar and RSS have their own agenda.

4.00 P.M.

We know that the Samata Party of Mr. Fernandes has its own agenda. That is a one-pointagenda—the Bihar Government should be dismissed. Another partner of the Government, the AIADMK leader of Tamil Nadu, has an agenda. What is her major agenda? Dismissal of the Karunanidhi Government. That is her agenda. Another leader, the leader of the Trinamul Congress from West Bengal, is also a part of the Government. What is her agenda? "Dismiss the Jyoti Government," These are the agenda of these people, besides, the other agenda.

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): They have forgotten the Indian agenda.

SHRI E. BALANANDAN: What about the agenda of the Sangh Parivar? Their agenda has only one item. What is that? Hinduvisation of the Indian society.

Sir, Christianity came to India in the First Century. Now, we are talking in the Twentieth Century. And, what is the proportion of Muslims? Except Indonesia, the largest Muslim population is in India, Bharat. In India, our Constitution has given protection to all. These people find enemies now? Who are the enemies? The minorities: Muslims are enemies; Christians are enemies. Another enemy is there—I do not want to name-according to Golwalker's theory. But the point is, as soon as they came to power, their immediate agenda came—to construct a temple in the disputed site. Because of the exposure that came from this House and the people of India, they had to, for the time being, put it off. Then came the issue of implementation of Justice Krishna Commission report which is not implemented. And, one fine morning, they found that the Bengali people who were working in Bombay for long were supposed to be Bangladeshis. They immediately picked them up and put them in the train to be transported to Bangladesh. The opposition came from this House and the West Bengal Government, that was also temporarily shelved. Then the agenda was of constructing another temple at Mathura demolishing the Muslim set-up there. A Committee has been formed. It goes on like that. A continued propaganda against Muslims is going on.

My hon. friend, Shri Manmohan Singh, has already spoken about the latest events. I do not want to go beyond that. But, at the same time, what exactly is the situation? A claim is being made that forcible conversions are sought to be made be Christian missionaries. There might be a stray case or two. But the population ratio shows that for the last ten years, the proportion of the Christian community is coming down. They say there is forcible conversion. Then how does the percentage of the Christian community come down. How does the equation go wrong, if that allegation is true? About Gujarat, I myself raised a question here in this House. Everybody was rather moved. Not only this section or that section. Everybody in the House was moved. Schools were attacked; Bibles were burnt; children were beaten; it went to the extent of beating priests and demolishing schools! It was a big issue. The Prime Minister went there, very good. We thought that when the Prime Minister went to attend to the problem, he would make a correct appraisal and take a correct attitude.

To our bad luck, Shri Atal Bihari Vajpayee, the respected Prime Minister of India, had gone to see the place where

the incidents of attack on the Christian community had taken place. What was the statement made by the Prime Minister afterwards? He has made an astonishing statement that nobody could understand. The statement was made that the conversion question needs to be locked into. The main plank on which the attack on the Christian community was justified by the Sangh Parivar was that there were forcible conversions. The Prime Minister had made a statement after visiting that this question needs to be looked into. What more they want? He was trying to give a certificate to them. That was not expected from the Indian Prime Minister who is supposed to be standing on a high pedestal. However, Mr. Vajpayee has done that. Sir, is this an issue relating to Muslims and Christians? No, Sir. This is an issue relating to India, the Indian unity, the Indian secular foundation and we have such a system where we have the Congress party, the Communists, the B.J.P. and other parties. We have different parties in India and we have our own programmes. We have so many things. But basically we are Indians. We want Indian unity to be kept even at the cost of lives. So, that is the main thing we have to protect and safeguard. What is being done is against the unity and integrity of India. If this agenda of the Sangh Parivar is allowed to continue, what will be the fact of the country? In all the important and essential sectors of Government, we find big R.S.S. ideologues being put in position, in the educational institutions, etc. By using that lever can be country be developed into this or that nature? The basic lever is education and culture. That lever is being used to communalise the situation and communalism is being introduced into the curriculam. To what extent is it being done? I do not want to explain that. Nathuram Godse had killed Mahatma Gandhi. It was known to all. Now, they say that these name of Mahatma Gandhi should be removed from the text books. In his place, the name of Nathuram Godse should be inserted in the text books. This is the extent of the orization being coming into the educational curriculum. The B.J.P. Ministers want to do it. This is a small thing. Education is not a Private affair of a political party. This is the question of India's unity as such. Therefore, the first point I want to make is that the Presidential Address this time has not addressed itself to this issue at all. This issue can create a very serious situation, a situation which can only be considered as nightmarish because we want freedom, we want to protect the unity and integrity of our people as well as our country. If the present trend is not checked, it will smash the unity and integrity of the country into pieces. Hitherto, the Government was posing a question that 'we only go with this agreed agenda.' Every day, a demand is made for convening a meeting of the Coordination Committee, this committee or that committee. There is no time left for the Government, to really govern the country. Every day is spent in appearing this party or that party, in considering this demand or that demand. This is how things go on. And, finally in Bihar, the democracy has been murdered. The ruling paty itself was, in the first place, divided. I do not know what kind of patch-up is being done now. What is the situation now? If we take the question of law and order which is breaking down, the big landlords of Bihar, who were owing allegiance to the Sangh Parivar, decided to kill the agricultural workers who were making some demands and fighting for their land and wages. They thought it fit to have their own private organisation, private sena. It was started during the period of the erstwhile Chief Minister. It continued during the period of the lady Chief Minister.

They purposely killed dozens of people on that day. Can it made an alibi for dismissing he Government? If that plea is to be taken, then any Government can be dismissed. A Government can be dismissed if somebody kills somebody.

This is absolutely putting the law in the reverse gear. It is a violation of the Consitutional provisions which also become a casualty under the BJP-RAJ. Therefore, the question now is as to how the secular foundation of the country is to be protected, as to how India's unity is to be protected.

The democratic set-up is being tampered with to placate their allies. This is the major demand of Mr. George Fernandes. Sir, what did Mr. Fernandes want? "I want that Government to go!" These people make such a demand. A majority of the people of Bihar, a majority of the people of West Bengal and a majority of the people of Tamil Nadu voted for their respective Governments. And somebody who has got 25 votes or a party which has got a small representation is supporting them, at the Centre being a peculiar situation, they are having some kind of the State Governments. On account of their demand, what kind of a situation has arisen? This is an abnormal situation. This is not a normal situation. When such an abnormal situation has arisen, what should be the attitude of everybody? When an abnormal situation has arisen, when the national unity and integrity and the basic foundation of our Constitution are at stake, every political party, every politically conscious man should come closer to see that the secular foundation of our Constitution is protected, the national integrity is protected and the democratic set-up is protected. This is the situation we are facing today.

Sir, the President has referred to a big event, i.e., the Pokhran nuclear blasts on May 11 and 13. We can discuss it. I must say that the nuclear capability which we have acquired has not been created by the BJP Government in just 30 days. Is it so? In 1974 itself, we had acquired this capability, and, after acquiring the capability, we said, "We don't want to go in for an arm's race. We don't want to go in for nuclear weapons." But we are also not going to be cowed down to sign on the dotted lines as imperialist countries or those who are having nuclear weapons, demand."

We wanted equality; all the nations should have an equal standing. Somebody can have huge stockpiles of nuclear arms; and they are preaching to us that we should immediately destroy them; what we should do etc. The do's and dont's are being dictated tous by those people, those countries which are having an abundance of nuclear weapons. We cannot agree. India is persistently continuing a policy which has been acclaimed the world over. And the policy pursued by the Government of India was a national policy. It is not a party policy. That national policy has been acclaimed by everybody. Now, as soon as the BJP came, they have done this rather quickly. And they said, 'we have become a nuclear power.' After seven days, we found that Pakistan also did the same thing. Then, what is the result? The result is that tension built-up between India and Pakistan. Was it necessary? Also, the imperialists used this occasion to deny us technical aid; deny us many important supplies which were needed for our national development, saying that we have gone beyond some limits. They wanted to impose economic sanctions against us to which we, Indians, cannot submit. We have to fight those things. But we have to understand our mistakes. If we do this kind of an experiment, then what will be the economic fall-out of this? This question has to be looked into separately; I don't want to deal with it here. But this is a question which puts upon the Government a lot of financial burden. In this strained economic situation, this ought not to have been done. Now, to repair the wounds, some steps are being taken like travelling to Lahore by bus, etc. We have no complaint against it. But at the same time, the whole situation has been created like this. Indo-Pakistan relations ought to be normalised by mutual discussion. Even after going and coming, the engine is still at the old station.

However, we cannot forget this question. The Government at the Centre dealt with this kind of a sensitive matter without proper consideration. It is a sin and crime on their part. The National Security Council has raised another question. As I told you, this country is a big country. Many political parties are there. National security is not the private affair of the BJP. The Chief Minister of every State should have some say in the National Security Council. This is a big nation. National security is an important subject. Before any crucial decision is taken, it has to be discussed fully with all the Chief Ministers, who are also elected by their people. We should have a properly-constituted National Security Council; a national security apparatus. That also has been done by the BJP as if it is its own private affair. As a fall-out of the Pokharan blast, pressure is coming on us and the economy is also facing a serious strain. The imperialist powers and the world economic powers put pressure on the Government of India to sign the CTBT on the dotted lines. This is the danger we are facing today.

Now I want to come to some questions about the price rise and the economy. What exactly is the situation today? Now, the Government claims that the economy is facing difficulties and that it is taking steps to improve the economy, etc. Comparing our country with the developing countries in the world it claims that our economic growth rate is high. What about the prices of essential commodities? I don't want to repeat the story of onions. You know about that story. We exported onions at Rs. 4 or Rs.5 and we imported onions at Rs. 20 or Rs.25. That is how this Govenrment manages the economy of this country. What happened? The essential commodities Act. That Act has been relaxed and a traders' paradise has been created. The big traders found that the production of certain essential commodities was becoming bad. They immediately hoarded things and the prices of everything went up. What is the latest situation? What is the step that the Government is taking now? The finance Minister wanted, before presenting the Budget, on the basis of the fiscal deficit development, to curtail fiscal deficit by cutting subsidies. The Government in its wisdom cut the subsidy. Subsidy to what did it cut? It cut the subsidy given for providing rations like rice, wheat, sugar, etc., to the weaker sections of the society. The price of urea had also been jacked up. How sensibly it is acting. As Soon as this Government came to power the economic policy became a bullshit. Huge concessions were given to the capitalist class. At the same time, it wants to take away whatever little concessions which are given to the common man. This is the approach of the Government in this regard. Therefore, the policy-makers and the Government are putting the people of the country to starvation. Many of the essential commodities are not within the reach of the common man. What is the result in totality? The result is that the people living below the poverty line are on the increase. As per the CSO estimates, the percentage of people living below the poverty line has increased from 29.1 to 32.93 during the period 1991-96. There is an increase of 3.2 per cent. In other works, 96 lakhs people are coming below the poverty line annually. It is nearly one crore. What is the meaning of the claim that the economy is progressing? The economy of a large section of the people is going down. Their life is going down and down. This is one of the results. In the case of the wages of the workers in the organised sector, the growth is negative. There is negative growth. When the prices go up, when you do not compensate the price rise, the growth in wages automatically becomes negative. There is a negative trend. Not only that, according to Government calculations, there is a surplus of 45 lakh workers in the organised industries. Therefore, the point I am making, Sir, is that the quality of

life of the people is going and down. The Workers' wages are going down and workers' employment is also going down. In this situation, the Government is going ahead with their so-called economic policy of globalisation. What is the total position of our economy? I do not want to go into the details of the economy as such because it can be dealt with some other time also. But the point is the agricultural output is expected to grow by 1.2 per cent during 1999. And that is possible because, in the year 1997-98, the food production was negative by 4.5 per cent. It is now positive from the negative side it has come a little to the positive side. That is the position now. The foodgrains production during 1998-99 is projected to grow by 0.1 per cent. During 1999, the *per captia* availability of foodgrains was expected to decline by more than eight kilograms per annum despite consecutive good nonsoons. So, availability of foodgrains has come down, and the industrial production is expected to be 3.2 per cent. I do not know what concocted figures will come in the Budget, but the point is, if it was 6.2 per cent last year, it is going to come down like that. That means, the economy is going into a very bad shape. So, my point is this. Dealing with the present economic situation, the President has said, that the global economic situaion is bad and inspite of the global environment, out economy is faring well. What is the global experience? You have talked of many countries as models of economic growth. The East Asian countries were supposed to be economic tigers. The second strongest economy is Japan. All these economies are facing a crisist. Why? Are they not following globalisations? Are we teaching them globalisations. They are masters; they are teaching us. But the national economy, as a whole, is facing a crisis. Therefore, the Government of India ought to have atlease taken a lesson from small countries like Mexico or Malaysia or for that matter, even Korea. Let us see about the World Bank. Now the World Bank does now stand for a total opening up. They are not saying that it is essential to see that the intrusion of the bubble economy is restricted. What does it mean by bubble economy? The speculative capital which has come into the country is now being withdrawn within no time, by those who have put in money. The country's economy is now being put into difficulty. Here, the question, Sir, is that this Government is the only Government in the World which did not study anything about the economic development. If at all they had studied, the will not say that it should be opened up; It is should be hundred per cent privatised, all the multi-nationals are welcome etc. The way the public sector industries are being considered and painted by the Government authorities is very bad. I have no time to go into all the details. For the last three consecutive years, the net profit of public sector companies has been going up continuously. In 1994-95, it was Rs. 12,000 crores. In 1995-96, it was Rs. 13,704 crores and in 1996-97, it was Rs. 16,120 crores. This is the profit which was earned by the public sector. Their contribution to the exchequer is more than the private sector. The public sector has paid Rs. 26,400 crores to the exchequer in the form of divident, corporate tax, income tax, excise and customs duty, etc., while the private sector has paid only Rs. 2,085 crores. So, the public sector being painted very bad, is not correct. I do not want to go into the details.

Disinvestment has been made a permanent feature here. But because of such a bad economic situation in the country, no body came forward to buy the shares. Therefore, the target of Rs. 5,000 crores could not be achieved. Then what is the ingenious method being resorted to by the Finance Minister? That method is buy-back system. What does it mean? The Navaratana companies which are the best companies in India and which can be ranked as first or second in

the world, are having some money for their working capital and future investment. Our Finance Minister thought it fit to take that money and asked those public sector companies to buy-back the Government shares. That means they are demanding the money which they are having so that these companies also become sick. This is the technique which is being usurped.

You are destroying the whole thing we have built. Sir, Rs. 2,00,000 crores which have been spent in the public sector are slowly being transferred to the private hands, i.e. Indian and foreign, for a song. This is not a small thing. I must say that it is a crime which cannot be pardoned. When India became independent, we were a poor country. We could not afford to develop the infrastructure. Then we started a public sector system. Sir, I don't want to go into the history. But within eleven months, in continuation of the policy, this Government wants to see to it that the whole thing is transferred to private hands. All the airports, Mumbai Airport, Delhi Airport, Calcutta Airport, Madras Airport, etc. and all the major ports, Cochin Port, Mumbai Port, Calcutta Port, Madras Port, etc. are being privatised, through corporatization. That is the situation now. They are also thinking of slowly privatising the governance itself by bringing the so-called experts from IMF and the world Bank. This is an absolutely unwanted position which will ruin the country. I would like to warn the Government.

Then some thing is coming up for the working class. According to the President's Address, a second Labour Commission is already appointed. That Commission is going to take steps to examine the existing laws and to make new laws, etc., in tune with the international economic development. Things are changing fast.

In tune with the changes the laws should change. Many changes are taking place the world-over. Take the case of Germany and other countries. I have gone through the economics of various countries. What is at stake is, workers' employment is being made unsafe. Absolute 'Hire and fire' right is sought to be given to the employers. That is the main contention now. The new economic development, which is also called jobless growth. There is no growth of jobs. They want to sent the workers out whenever they want, and the workers' duty time, their permanency, etc. are not being taken care. The working class of India are not easily going to submit to these things. Sir, before concluding, I want to mention one or two things more. On the international scene, there are international agreements with SAARC countries as well as Ceylon. 'Opening up' is the catchword today. I am from Kerala. Kerala and Ceylon have more or less the same climate. Our economy, Kerala's economy, is mainly based on cash crops. The main cash crop is rubber. The Government is purposely importing rubber. We are having self sufficiency in rubber. Every nation in the world, while they might say that they are for complete liberalisation, take conscious steps to protect their industries and their agriculture. Without that, no country is playing today. The only exception is our Government, the BJP led Government. When we go in for liberalisation, we don't want our to be closed down to the advantage of others. We don't want our agriculture to suffer, and others to gain. In Kerala, the economy is in doldrums, because the cultivators cannot do anything. Now, the rubber plantations are not able to employ workers to get the rubber tapped. Tapping cannot be done because they cannot pay wages to the workers. This is one thing. Another thing is that we have another cash crop which is also being produced in Ceylon. What is the advantage of general agreements, etc? I am not going into all that. But what is the effect on the country, especially on our State? We told our Commerce Minister that while they go in for these things, our country's interests should be taken up primarily. That is their duty. But they did

not take it up and did not consider it seriously.

Sir, I want to conclude by saying one thing about the handling of industries by the Government. They are taking steps to close down our industries. This is known to all. For example, I would like to quote something which was said by the Industries Minister in this House. The Minister of Industries, in a statement made in the Rajya Sabha on 1.12.98 — this is on record — said that the Government would not stand in the way of eventual revival of any of these PSUs if the revival scheme is sanctioned."

For how many companies? For nine companies, employing ten thousand workers. These companies are Mining and Allied Machinery Corporation Ltd. (MAMC), National Bicycle Corporation of India Ltd. (NBCIL), Cycle Corporation of India Ltd. (CCIL), Bharat Ophthalmic Class Ltd. (BOGL), National Instruments Ltd. (NIL), Weighbird India Ltd. (WIL), Bharat Process and Mechanical Engineers Ltd. (BPME), Tannery and Footwear Corporation of India Ltd. (TAFCO) and Rehabilitation Industries Corporation of India (RIC). The Minister assured that he had no objection to the revival of these units. This statement was made on 1.12.1998. These units were given an ultimatum to accept VRS/VSS by 28.2.1999, that is, after two months. Now, the Government says that they are not doing anything. When you are in the Government and you make a statement in the House, you should be serious about it. When the Government says something, it should be implemented. The Workers' case has to be very carefully handled. That is not being done. I do not want to go into the details of this statement. But the point that I want to make is that the pubic sector privatisation, the attack on the working class, the attack on the economy and the attack on the national interest is not to be tolerated by anybody. Therefore, with all respect to Vajpayeeji, the first thing I demand is, please get down, clear out, so that India can be saved.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri Sangh Priya Gautam.

श्री संघ प्रिय गौतमः उपसभाध्यक्ष जी, माननीय प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा जी ने आदरणीय राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए वक्तव्य के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। उपसभाध्यक्ष जी, भारत एक विशाल देश है। इस देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्म, जाति, सम्प्रदायों के लोग हैं और इस देश की बहुमुखी समस्याएं हैं और देश के सामने बड़ी कठिनाईयां हैं। आबादी बराबर बढ़ रही है। एक समय ऐसा आया कि खेती उत्पाद में भी कमी आई, उद्योग के उत्पाद में भी कमी रही, काला धन निकल नहीं पाया, अनगिनत धन विदेशों से आ नहीं पाया और आबादी पर कोई रोक नहीं है। सरकार कोई भी रहे यह आर्थिक कठिनाईयों के संकेत हैं चाहे किसी दल की सरकार रहे।...(**व्यवधान**) Kinhdly listen to me.

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, आप बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतमः ऐसी परिस्थितियों में इस सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह प्रशंसनीय है। उसके दो कारण हैं। पहला तो इस कारण से कि यह पहली सरकार है जो गैर कांग्रेसी सरकार है। इस देश में जितने प्रधान मंत्री हुए या तो वह...(**व्यवधान**)

श्री रामजीलालः यह सरकार पहले भी आई थी।...(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतमः तो हम कम नहीं हैं। ...**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गौतम जी, हां बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतमः इस देश में जितने प्रधान मंत्री हुए यह तो वह कांग्रेसी थे या कांग्रेस से बाहर आए हुए कांग्रेसी थे। यह पहले प्रधान मंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी हैं—एक बात। दूसरी बात, जब-जब चुनाव हुए तो इस देश के राजनीतिक दलों ने संयुक्त रूप से यह प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीतने पाए। अगर खुदा-न-खास्ता चुनाव जीत करके पूरे बहुमत में कोई दल नहीं आया लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल उभर कर आया, तो संयुक्त रूप से यह प्रयास

हुआ कि भाजपा की सरकार बनने न पाए। अगर किसी तरह सरकार बन भी गई तो यह प्रयास हुआ कि विश्वास मत नहीं प्राप्त करने पाए।

अगर विश्वास मत प्राप्त कर भी लिया तो यह प्रयास हुआ कि सरकार चलने नहीं पाए और अगर सरकार चल गई तो किसी तरह से अस्थिर की जाए और एक प्रोपेगेंडा किया जाए कि सरकार जा रही है। इन परिस्थितियों में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रपति जी के भाषण के बारे में कुछ चर्चाएं सेंट्रल हॉल में हुई कि बड़ा लंबा भाषण था। प्रस्ताव, बहस या बयान का छोटा या बड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह तथ्यों पर आधारित है या नहीं। राष्ट्रपति जी ने इस देश की बहुमुखी समस्याओं को उजागर करते हुए कहां तक हम पहुंचे हैं और क्या हमें करना है, उन सब का उल्लेख किया है इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दूरदर्शिता और विशाल हृदयता का परिचय दिया और यह कहा कि स्वतंत्रता के बाद सरकारें चाहे कोई भी रही हों, इस देश ने उपलब्धियां की हैं और उस पर हमें गर्व है। यह राष्ट्रपति जी ने कहा। सरकारें कांग्रेस की भी रहीं, सब सरकारों में उपलब्धियां हुई हैं। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर सभी सरकारों द्वारा स्वतंत्रता के बाद जो देश को उपलब्धियां हुई हैं, उस पर गर्व व्यक्त किया है और जो काम अधूरे रह गए हैं, उन्हें हम मिल-जुल कर पूरा करें, इस तरह की अपील और संवेदना व्यक्त की है। यह विशाल हृदयता का और दूरदर्शिता का परिचायक है। मोटे तौर पर मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे मित्रों ने कहीं हैं लेकिन चार-पांच क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है आर्थिक क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि उत्पादों पर आधारित रही है। पहली बार कृषि क्षेत्र में इस सरकार ने पिछले बजट का 58 परसेंट पैसा आबंटित करके उस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया और जितने भी...(**व्यवधान**)... मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि आप मुझे बोलने दें अगर नहीं मानेंगे तो आपको (**व्यवधान**).... मैं कभी बोलने नहीं दे सकता, मैं नहीं चाहता हूं कि टकराव की स्थिति बने ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरोज दुबे: महोदय, इन्होंने चुनौती दी है कि हम बोलने नहीं देंगे। हम इनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं।...हम इनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैडम, बैठिए...बैठिए ना। गौतम जी, आप बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभाध्यक्ष महोदय, खेती के क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन मिले, किसानों को सुविधा मिले, किसानों की लागत और मेहनत से पैदा की हुई फसल अगर नष्ट हो जाए तो वे विलाप न करें, उसकी फसल का बीमा हो, इस प्रकार के निर्णय इस सरकार ने लिए हैं।

महोदय, जहां तक उद्योगों का सवाल है, उद्योग जीवित हों, उद्योग पुनर्स्थापित हों, उद्योगों में पूंजी निवेश हो, यदि नहीं चल रहे हैं तो कानूनी तरीके से उनकी बिक्री हो, इसके ऊपर इस सरकार ने निर्णय लिए हैं। उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों के सलाह-मशविरे से आर्थिक क्षेत्र में सुचारुता लाने के लिए परामर्शदात्री समितियों का निर्माण किया। आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम इस सरकार ने उठाए।

दूसरा क्षेत्र है सामाजिक। सामाजिक जन-कल्याण के लिए आवश्यक शिक्षा और वह भी महिलाओं के लिए शिक्षा, 14 वर्ष के छात्रों को शिक्षा मिले, विद्यालयों का निर्माण हो, विदयालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हो, इस तरह का निर्देश और सहयोग प्रत्येक राज्य को दिया और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा लोग शिक्षित बनें, ज्यादा लोगों को शिक्षा मिले, यह एक ऐतिहासिक काम किया। महिलाओं को बी०ए० तक की शिक्षा मुफ्त मिले, यह हमारे सामाजिक क्षेत्र में, पिछड़े हुए क्षेत्र में एक प्रशंसनीय कार्य है।

हर व्यक्त यह चाहता है कि उसका सिर छिपाने के लिए एक छोटा-सा मकान हो। इस देश में करोड़ों लोग बगैर घर के रह रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 20 लाख मकान निर्मित हों, यह निर्णय लिया है। जब मकान निर्मित होंगे तो उनमें सीमेंट भी लगेगा, लोह भी लगेगा, ईंटा भी लगेगा और भी पदार्थ लगेंगे। जो लोहे में आज मंदी आई है वह मंदी भी खत्म होगी, सीमेंट में जो मंदी आई है वह मंदी भी खत्म होगी, जो ईंटा में मंदी आई है वह मंदी भी खत्म होगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि श्रमिकों को रेजगार मिलेगा और इस देश में रोजगार बहुत आवश्यक है। इसलिए मकान बनाने से कई उद्योग सुधरेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसके बाद हमारे देश की सुरक्षा की बात आती है चाहे वह आंतरिक सुरक्षा हो या

बाह्य सुरक्षा हो। आंतरिक सुरक्षा के लिए सरकार ने अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर जो उचित निर्णय हो सकते थे वह निर्णय लिए। हमारा देश दुनिया की निगाह में एक शक्तिशाली देश हो और उसकी तरफ कोई अंगुली न उठा सके, इस क्षेत्र में परमाणु विस्फोट करके पोखरण का एक ऐतिहासिक काम किया है, देश को स्वाबलम्बी बनाया है। लोग कहते थे कि हम आर्थिक क्षेत्र में पीछे चले जायेंगे और दुनिया के देशों से हमारी दुश्मनी हो जाएगी, जबकि हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान आज हमारे साथ भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमारे निकट बहुत तेजी से आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान और भारतवर्ष के मेल के प्रयास की, माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के पाकिस्तान जाने की सराहना कर रहा है। उसने उसकी प्रशंसा की है। सुरक्षा के क्षेत्र में हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हमने अपने वैज्ञानिकों के मनोबल को बढ़ाया है, हमारा अनुसंधान कार्य भविष्य में भी जारी रहे, सिसे हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि पड़ोसियों से अपने संबंध अच्छे हों, इन संबंधों को सुधारने में हमने सफलता प्राप्त की है और पूरा प्रयास हमने इस क्षेत्र में किया है।

अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और जनजाति जो समाज के सबसे कमजोर अंग हैं, उनके लिए हमने अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम और पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम इन तीनों की धनराशि को तिगुना किया है। यही नहीं, इस मंत्रालय का नाम जो समाज कल्याण मंत्रालय था उसका नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रखा और मंत्रालय का नाम ही नहीं बदला बल्कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सत्ता में हो यह काम भी किया। कांग्रेस द्वारा पहले दो राज्यपाल नियुक्त किए हुए थे अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा के। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का समय पूरा हो गया, उसको तो सरकार ने हटाया नहीं बल्कि और दो अनुसूचित जाति के राज्यपाल उत्तर प्रदेश और मिजोरम के नियुक्त किए। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तो वहां पर भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव श्री माधव राव गोडबोले को सलाहकार बनाकर भेजा गया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इन जातियों के जजों की नियुक्ति नहीं होती है। यह जो हमारी व्यवस्था है यह सही नहीं है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए इस सरकार ने अपने राष्ट्रीय ऐजेण्डा की धारा 23 में यह निर्णय लिया कि हम एक नेशनल जुडिशियल कमीशन स्थापित करेंगे और उसके द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए संस्तुति होगी। जजों के लिए आचार-संहिता भी वही बनाएगा। इस दिशा में इस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति, जन-जाति और पिछड़ी जातियों को यही नहीं बल्कि उनके आर्थिक क्षेत्र में विकास को आबादी के हिसाब से स्पैशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत पैसा उनपर खर्च होना ही चाहिए। अनेक राज्यों में वह धनराशि उन पर खर्च नहीं हुई। या तो वह दूसरी मदों में खर्च कर दी गई या बिल्कुल खर्च नहीं की गई। मुझे दुख है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम और बिहार में तो एक पाई भी खर्च नहीं की गई।...**(व्यवधान)**... मैं कह रहा हूं कि यही नहीं धारा-339(2) अनुसूचित जनजातियों के बारे में कहती है कि अनुसूचति जनजाति या अनुसूचित जन क्षेत्र के लिए एक स्पेशल कांउसिल होगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद-5 की धारा चार की उपधारा एक है कि यह कम्पलसरी होगा। केन्द्र सरकार को तो यह अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार को डायरेक्शन देगी और स्टेट गवर्नमेंट शेल कांस्टीट्यूट एकांउसिल। बिहार में अनुसूचित जनजाति जो झारखंड क्षेत्र में है, वहां विकास परिषद् स्थापित की गई। वह संवैधानिक है लेकिन इस सरकार ने उसको समाप्त कर दिया और असंवैधानिक काम कर दिया। इसलिए भारत सरकार ने निर्देशित किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की धनराशि आवश्यक रूप से समय के तहत इन वर्गों पर खर्च करनी पड़ेगी। जो पैसा पहले से दिया गया है अगर उसका उपयोग तब तक नहीं होता है तो दूसरी किश्त किसी भी सरकार को नहीं दी जायेगी। यह गारन्टी की है, यह एन्श्योर किया है कि इन वर्गों के आर्थिक उत्थान के लिए इन पर यह धन राशि खर्च होनी ही चाहिए। उनके आर्थिक विकास के क्षेत्र में यह ऐतिहासिक कदम इस सरकर ने उठाया है।

मान्यवर, यही नहीं इन वर्गों को सत्ता में भी भागीदारी मिले। जिस पार्टी की यह सरकार है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक दलित महिला को दो बार मुख्य मंत्री बनाकर व्यावहारिकता में इस बात को सिद्ध किया कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को सत्ता में भागीदारी देती है जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। जिनसे समझौता था उन्होंने सत्ता में भागीदारी नहीं देने दी। जो मिल-जुलकर सरकार चला रहे थे, उन्होंने अर्थ-विहीन मुद्दों पर तो समर्थन वापस ले लिया। मगर यह एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेसी भाई यह भी कह सकते थे कि

संयुक्त मोर्चे वालों अगर तुमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनवाई तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। अगर यह कहते तो ये दलितों के हितैषी भी कहलाते और उनकी भागीदारी भी हो जाती। लेकिन ये तो घड़ियाली आंसू बहाते रहे मगर भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग को सच्चे मायने में सत्ता में भागीदारी दी। महोदय, शुड आई कन्टीन्यू आलसो?

THE VICE -CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): That I will tell you. आज का काम आज कीजिए।...**(व्यवधान)** अभी पांच नहीं बजे हैं। आप बोलिए। गौतम जी, अभी दो मिनट हैं, आप बोलिए।

श्री संघ प्रिय गौतमः महोदय, इसके अलावा अनुसूचित जाति, जन जाति और अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से भागीदारी मिले, अभी बिहार में एक अल्पसंख्यक रिजवी साहब को सलाहकार बनाकर भेजा है। यही नहीं जो अल्पसंख्यक राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य के थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन उनको नहीं हटाया। उनको रिपीट किया। यह मैं आपको बता रहा हूं कि भागीदारी किस तरह से यह सरकार अल्पसंख्यकों की सुनिश्चित कर रही है। ये कुछ उदारहण हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now, it is 5 O' clock. I adjourn the House till 11.00 am tomorrow.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 25th February; 1999.

MGIPRRND—2354 GIPMR/99—300 Copies.